घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 213- गुरूवार 04 - जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली में 6 मंजिला होटल में लगी आग

21 की मौत

मरने वालों में ज्यादातर विदेशी, 40 को बचाया

जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग

नई दिल्ली,03 जून 2026। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लरिश स्टे नाम के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से हैं। कितने विदेशी नागरिक मारे गए हैं,फिलहाल इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीयों लोगों के मुताबिक,मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8.50 बजे आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। घटना के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी-चौथी मंजिल से कूदते नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। कुल 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कई लोगों की हालत गंभीर है। वहीं, बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। दिल्ली के इस होटल में आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग-अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है।

सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख बोलीं-सरकार प्रभावित परिवारों के साथ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में हुई जान-माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की और इस हृदयविदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति व साहस मिलने की प्रार्थना करती हूं। 'उन्होंने आगे लिखा, 'घटना की सूचना मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा,दिल्ली पुलिस,डीडीएमए,सीएटीएस एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय किया गया और बचाव व राहत कार्य शुरू किए गए। उनकी त्वरित कार्रवाई की मदद से प्रभावित परिसर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दुख की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा,'हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने मालवीय नगर अग्निकांड पर दुःख जताया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु,उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेस्टोरेंट में आग लगने से 21 लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मु ने एक्स पर पोस्ट कर मालवीय नगर अग्निकांड पर दुख जताते हुए कहा कि इस घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की साथ ही घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आग में लोगों की मृत्यु पर दुःखद जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि दुख की इस घड़ी में उन्हें शक्ति और साहस मिले। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कई अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मालवीय नगर अग्निकांड को हृदयविदारक बताते हुए इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

दिल्ली पुलिस ने बताया होटल मालिक का नाम लोकेश बजाज

दिल्ली पुलिस के अनुसार होटल का मालिक लोकेश बजाज है। होटल का संचालन तीन पार्टनर मिलकर करते हैं। इन लोगों के दिल्ली में कई अन्य होटल और गेस्ट हाउस भी हैं। पुलिस अब होटल के मालिकाना हक, संचालन और फायर सेफ्टी इंतजामों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई।

रेस्क्यू के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल

दिल्ली पुलिस के अनुसार,मालवीय नगर अग्निकांड में बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 5 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक,ये सभी सबसे पहले इमारत के भीतर प्रवेश कर राहत और बचाव कार्य में जुटे थे।

ममता की टीएमसी टूटी...58 विधायकों ने अलग गुट बनाया

ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना

कोलकाता,03 जून 2026। पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में फूट पड़ गई है। सोमवार को पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने विधायक दल का नेता घोषित किया। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से मिलकर समर्थन पत्र भी सौंपा। जावेद खान, संदीपन साहा और सिउली साहा को उपनेता बनाया गया है। वहीं अखरुज्जमान को चीफ व्हिप बनाया गया है। बंगाल में हुए चुनाव में टीएमसी ने 80 सीटें जीतीं थीं। 58 विधायकों की बगावत के बाद अब ममता के पास सिर्फ 22 विधायक बचे हैं। हालांकि बागी गुट ने अपने पत्र में ममता बनर्जी को अब भी पार्टी अध्यक्ष बताया है। लेकिन वे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और विधायक दल से जुड़े फैसलों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोमवार को अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर स्पीकर को भेजे गए पत्र में शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव भेजा था। विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने शिकायत की थी कि इस प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। शिकायत के बाद ममता ने दोनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

ममता ने पार्टी कमेटियां भंग कीं...

पार्टी के भीतर बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी अब पूरे संगठन का पुनर्गठन करेगी। ममता बनर्जी ने टीएमसी से 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया था। दोनों ने स्पीकर से शिकायत की थी कि पार्टी ने शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने वाले प्रस्ताव में उनके उनके फर्जी साइन किए थे। साहा और बनर्जी का आरोप है कि यह शिकायत करने पर ही दोनों टीएमसी से निकाले गए।

कर्नाटक के 25वें सीएम बने डी.के. शिवकुमार

संविधान हाथ में लेकर ली शपथ,सिद्धारमैया के बेटे समेत 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली

बेंगलुरु,03 जून 2026। डीके शिवकुमार ने बुधवार को बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान वे हाथ में संविधान रखे हुए थे। उन्हें 30 मई को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया था। जी परमेश्वर ने नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली। इनके अलावा 12 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया के एमएलसी बेटे यतींद्र सिद्धारमैया भी शामिल हैं। शिवकुमार, सिद्धारमैया की जगह राज्य की कमान संभालेंगे। सिद्धारमैया ने 28 मई को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक मुख्यमंत्री रहे।

शपथ में राहुल-खड़गे शामिल हुए : नई कैबिनेट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा केरल, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री और अन्य कांग्रेस नेता शामिल हुए। शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले सिद्धारमैया को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

डीके के पास 1400 करोड़ की संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ भी गए : कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर नेताओं में हैं। उनके पास 1413 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वह रियल एस्टेट, खनन, होटल कारोबारी हैं। इतनी संपत्ति के बावजूद उनके चुनावी हलफनामे में एक टोयोटा क्वालिस कार दर्ज है। 263 करोड़ का कर्ज भी है।

नीतीश कुमार की पार्टी ने बनाया इतिहास जदयू के सदस्यों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा

पटना,03 जून 2026। बिहार के सत्तारूढ़ एनडीए में प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने प्राथमिक सदस्यों की संख्या में एक इतिहास रचा है। जदयू का दावा है कि उसके प्राथमिक सदस्यों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद लगातार संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बुधवार को इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि एक करोड़ से अधिक सदस्यों वाले जदयू परिवार में आपका स्वागत है। उन्होंने जदयू के प्राथमिक सदस्यों की संख्या एक करोड़ होने की जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, 'हमें बताते हुए खुशी है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा 6 दिसंबर 2025 को शुरू किए गए 'जदयू सदस्यता अभियान 2025-28' के तहत एक करोड़ से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाने के पहले लक्ष्य को छह महीने से भी कम समय में हासिल कर लिया गया है। ' संजय कुमार झा ने आगे बताया कि 2 जून 2026 तक पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की कुल संख्या एक करोड़ एक हजार नौ सौ पच्चीस हो चुकी है।

कैबिनेट के फैसला...दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक-बस बदलने की 9,585 करोड़ की योजना को मंजूरी

नई दिल्ली,03 जून 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपये की दो वर्षीय योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहयोग दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पत्रकारों को बताया कि इस योजना को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत एनसीआरपीबी द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें भी भागीदार होंगी। योजना के तहत केंद्र सरकार 5,041 करोड़ रुपये देगी और राज्यों द्वारा लगभग 1,601 करोड़ रुपये कर रियायतों के रूप में दिए जाएंगे। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और टेरी की रिपोर्टों में बताया गया है कि परिवहन क्षेत्र से पीएम 2.5 का 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड का 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 63 प्रतिशत उत्सर्जन होता है।

केंद्र ने 10 हजार करोड़ के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को दी मंजूरी

पश्चिम एशिया में जारी संकट एवं वैश्विक ईंधन की कीमतों में उछाल के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस के लिए 10,000 करोड़ रुपये के एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य विमानन कंपनियों और यात्रियों को ईंधन के भारी झटकों से बचा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल विपणन कंपनियों को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एकमुश्त बजटीय सहयोग देने की मंजूरी दी है, ताकि वे अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों को उनके घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों को स्थिर रखने में सहायता प्रदान कर सकें।

संपादकीय

बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति

भारतीय लोकतंत्र आज एक गहरे सामाजिक और राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह परिवर्तन केवल संसद या चुनावी परिणामों तक सीमित नहीं है,बल्कि समाज की मानसिक संरचना, संवाद की प्रकृति और जनमत निर्माण की प्रक्रिया तक फैल चुका है। आज राजनीतिक विमर्श का बड़ा हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर आकार ले रहा है। जनमत अब पारंपरिक माध्यमों से आगे बढ़कर इंस्टाग्राम रील,यूट्यूब शार्ट्स, एक्स पोस्ट और वायरल मीम्स के जरिये निर्मित हो रहा है। इसी पृष्ठभूमि में काकरोच जनता पार्टी जैसी अचानक उभरी लोकप्रियता को केवल डिजिटल ट्रेंड मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह उस बेचैन युवा भारत की अभिव्यक्ति है,जो स्वयं को लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है।

समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो जब किसी समाज की मुख्य संस्थाएं-राजनीति,प्रशासन,शिक्षा और मीडिया जनभावनाओं से दूरी बनाने लगती हैं, तब नए प्रतीक और नई राजनीतिक भाषाएं जन्म लेती हैं। कई बार ये प्रतीक व्यंग्य के रूप में सामने आते हैं,लेकिन इनके भीतर गहरी सामाजिक पीड़ा और असंतोष छिपा होता है। काकरोच जनता पार्टी इसी डिजिटल युग का एक ऐसा ही सांकेतिक प्रतिरोध है। काकरोच एक ऐसा जीव है, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह जाता है।

यह प्रतीक आज के उस युवा मानस को आकर्षित करता है, जो बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितता, आर्थिक असुरक्षा और सामाजिक दबाव के बीच किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। दूसरी ओर, शिक्षित बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। आंकड़े लगातार यह संकेत देते हैं कि युवाओं में बेरोजगारी की दर औसत से अधिक बनी हुई है। लाखों युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं,लेकिन भर्ती प्रक्रियाएं या तो विलंबित होती हैं या विवादों में उलझ जाती हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक असंतोष का कारण बन रही है।

आज का युवा केवल रोजगार नहीं चाहता,वह सम्मानजनक भागीदारी चाहता है। वह यह महसूस करना चाहता है कि लोकतंत्र में उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन जब उसे मंचों पर केवल औपचारिक आश्वासन और इंटरनेट मीडिया पर केवल प्रचार दिखाई देता है,तब वह अपनी अभिव्यक्ति के नए माध्यम खोजता है। वर्तमान चुनावी परिदृश्य में यह प्रवृत्ति और अधिक स्पष्ट हो गई है। चुनाव अब केवल मतदान केंद्रों तक सीमित नहीं रहे,बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़े जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के डिजिटल अभियान,आइटी सेल और इंटरनेट मीडिया रणनीतियां जनमत निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं,लेकिन इस डिजिटल राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार अनुत्तरित है-क्या हम वास्तव में युवा भारत की मूल चिंताओं को समझ पा रहे हैं? आज का युवा पहले की तरह केवल परंपरागत राजनीतिक निष्ठाओं से बंधा नहीं है। वह प्रश्न पूछता है, तुलना करता है, तथ्य जांचता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। इंटरनेट मीडिया ने उसे अभूतपूर्व अभिव्यक्ति की शक्ति दी है। यह लोकतंत्र के विस्तार का संकेत है और उसकी नई चुनौती भी।

टूटते भरोसे के वेंटिलेटर पर देश की परीक्षा व्यवस्था

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

भारत में परीक्षा अब केवल योग्यता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णायक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार संदिग्ध हो जाए,जब मेहनत और ईमानदारी की जगह 'जुगाड़' और 'माफिया नेटवर्क' हावी हो जाएं,तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है। पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना,सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जीडी परीक्षा में धांधली,ये घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब गहरे संस्थागत संकट में फंस चुकी है और भारत की परीक्षा प्रणाली अब वेंटिलेटर पर है। नीट-यूजी 2026 का घटनाक्रम तो इस विफलता की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। लगभग 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और वर्षों की तैयारी एक झटके में शून्य हो गई। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था, जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार मामला केवल बाहरी गिरोहों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जांच में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर तक मिलीभगत के आरोप सामने आए।

सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्न-पत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। जिस संस्था को निष्पक्षता की गारंटी देनी थी,वही यदि धांधली का हिस्सा बन जाए तो पूरी व्यवस्था का नैतिक आधार ही खत्म हो जाता है। नीट पेपर लीक की प्रकृति भी सामान्य नहीं थी। 'गेस पेपर' के नाम पर लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का हूबहू मिल जाना,परीक्षा से पहले 600 अंकों तक के सवालों का प्रसार,व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम प्रश्नपत्र का घूमना,ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकते। यह एक संगठित, बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क का संकेत है,जो परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी को भेद चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में पेपर लीक के बाद भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों,जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है।

भारत की परीक्षा प्रणाली का ढांचा ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही वह जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जड़ें जमाता है। जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में फैल सकता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कागजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। दूसरी ओर, कोचिंग उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं अब हजारों करोड़ रुपये का बाजार बन चुकी हैं। इस बाजार में 'सफलता' एक उत्पाद है, जिसे

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया 'सीक्रेट पेपर', '100 प्रतिशत सलेक्शन गारंटी' और 'इनसाइडर एक्सेस' जैसे झूठे वादों के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट करता है। डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शिता और दक्षता बे ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन इसके परिणाम उलटे दिखाई दिए। पास प्रतिशत में गिरावट, मेधावी छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलना और स्कैन की गई कॉपियों में भारी गड़बड़ियां,ये सब इस बात के संकेत हैं कि तकनीक को बिना पर्याप्त तैयारी और परीक्षण के लागू किया गया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी कॉपियां धुंधली थी,कुछ को गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिली और कुछ मामलों में तो पूरी कॉपी ही किसी और की थी। यह स्थिति केवल तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती बल्कि यह सरासर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। यदि एक छात्र की मेहनत को किसी दूसरे की कॉपी से बदल दिया जाए तो यह केवल गलती नहीं है बल्कि उस छात्र के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड भले ही इन खामियों को सीमित मामलों तक बताकर पल्ला झो ने की कोशिश करें लेकिन छात्रों में बढ़ता असंतोष इस बात का प्रमाण है कि समस्या व्यापक है।

तीसरी बड़ी घटना,एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में धांधली,इस बात को और स्पष्ट करती है कि यह संकट किसी एक परीक्षा या संस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रैकेट ने इस धांधली के आधुनिक रूप को उजागर किया। प्रॉक्सी सर्वर, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा में हेरफेर किया जा रहा था। यह पारंपरिक नकल या पेपर लीक से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रणाली को भीतर से हैक किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक भयावह तस्वीर उभरती है,एक ऐसी व्यवस्था, जहां प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं,मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। सबसे अधिक पीड़ित वह छात्र है,जो ईमानदारी से मेहनत करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र, जिनके माता-पिता ने कर्ज लेकर या जमीन गिरवी रखकर उन्हें कोचिंग दिलाई, आज सबसे ज्यादा निराश हैं। एक परीक्षा रद्द होने का मतलब केवल दोबारा परीक्षा देना नहीं होता बल्कि यह मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और आत्मविश्वास के टूटने का कारण बनता है।

इस पूरे संकट का एक और खतरनाक पहलू है व्यवस्था के प्रति बढ़ता अविश्वास। जब छात्र यह मानने लगें कि सफलता मेहनत से नहीं बल्कि 'सेटिंग' से मिलती है तो यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी पतन है। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? क्या हर बार जांच, गिरफ्तारी और बयानबाजी से काम चल जाएगा? स्पष्ट है कि नहीं। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में पूर्ण डिजिटल और एन्क्रिप्टेड मॉडल लागू करना होगा। प्रश्नपत्रों को परीक्षा से कुछ मिनट पहले तक सुरक्षित सर्वर में रखा जाए और सीधे केंद्रों पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जाए। इससे छपाई और परिवहन से जुड़ी कमजोरियां समाप्त होंगी। दूसरा, आउटसोर्सिंग व्यवस्था को सीमित करना होगा। संवेदनशील कार्यों में केवल प्रशिक्षित और जवाबदेह सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा,पेपर लीक को संगठित आर्थिक अपराध घोषित कर इसके लिए गैर-जमानती कठोर कानून बनाए जाएं। जब तक अपराधियों को कठोर सजा नहीं मिलेगी, तब तक यह धंधा बंद नहीं होगा। चौथा,साइबर निगरानी को मजबूत करना होगा। टेलीग्राम, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए विशेष एजेंसियां बनाई जानी चाहिए। पांचवां, तकनीक को लागू करने से पहले उसका व्यापक परीक्षण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। सीबीएसई ओएसएम विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना तैयारी के लागू की गई तकनीक समाधान नहीं बल्कि नई समस्या बन सकती है।

सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति। जब तक सरकार इस समस्या को 'राष्ट्रीय आपदा' की तरह नहीं देखेगी,तब तक आधे-अधूरे समाधान ही सामने आएंगे। नीट-यूजी 2026,सीबीएसई ओएसएम विवाद और एसएससी परीक्षा धांधली, ये घटनाएं चेतावनी हैं। यदि अब भी कठोर और स्थायी सुधार नहीं किए गए तो आने वाले समय में हर परीक्षा संदेह के घेरे में होगी। तब सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि पेपर लीक हुआ बल्कि यह होगी कि देश के युवाओं का विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। और जिस राष्ट्र के युवा ही अपनी व्यवस्था पर विश्वास खो दें,उसके भविष्य की नींव कितनी कमजोर हो जाती है,यह समझना मुश्किल नहीं है।

जब मौत बन जाए सोशल मीडिया का कंटेंट

सोशल मीडिया पर हिंसक वीडियो का प्रसार : संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रश्न

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

हाल के दिनों में एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या और हांसी में एक दुकानदार की दर्दनाक हत्या से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से पोस्ट और शेयर किए जा रहे हैं। इन वीडियो की एक झलक मात्र ही किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की रूह कंपा देने के लिए पर्याप्त है। पूरे वीडियो को देखने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पा रहे हैं। जो भी इन्हें देख रहा है, वह उनकी भयावहता और अमानवीयता से विचलित हो रहा है। ऐसे वीडियो में न कोई संदेश है,न कोई सकारात्मक उद्देश्य,बल्कि केवल पीड़ा, भय और मानसिक असहजता है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री का खुलेआम प्रसार उचित है और क्या प्लेटफॉर्म्स को इसे तुरंत हटाने की जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए?

डिजिटल युग में सूचना का आदान-प्रदान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो गया है। कोई भी घटना कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। यह तकनीक का सकारात्मक पक्ष है,क्योंकि इससे लोगों को त्वरित जानकारी मिलती है। लेकिन जब इसी तकनीक का उपयोग किसी की हत्या, दुर्घटना या व्यक्तिगत त्रासदी के भयावह दृश्यों को फैलाने के लिए होने लगे, तब यह चिंता का विषय बन जाता है। सूचना और सनसनी के बीच एक स्पष्ट अंतर होता है। किसी घटना की जानकारी देना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उस घटना के वीभत्स दृश्यों को बार-बार प्रसारित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता।

जब किसी बच्चे की हत्या होती है या किसी व्यक्ति को बेरहमी से मार दिया जाता है, तब वह केवल एक खबर नहीं होती। उसके पीछे एक परिवार का दर्द,असंख्य टूटे हुए सपने और जीवनभर का दुःख छिपा होता है। ऐसे वीडियो वायरल होने पर पीड़ित परिवारों की पीड़ा और बढ़ जाती है। वे लोग जो पहले से ही अपनों को खोने के सदमे में होते हैं,उन्हें बार-बार वही दृश्य सोशल मीडिया पर देखने पड़ते हैं। यह उनके लिए मानसिक यातना से कम नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में मृतक और उसके परिवार की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए,लेकिन वायरल संस्कृति ने कई बार इस संवेदनशीलता को पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ वायरल होने की होड़ भी बढ़ी है। अधिक लाइक,व्यूज़,शेयर और फॉलोअर्स पाने की चाह में कई लोग बिना किसी नैतिक विचार के ऐसी सामग्री साझा कर देते हैं। कई बार लोग यह कहकर वीडियो पोस्ट करते हैं कि वे सच्चाई दिखा रहे हैं,जबकि वास्तविकता यह होती है कि वे अनजाने या जानबूझकर एक दर्दनाक घटना को डिजिटल तमाशे में बदल रहे होते हैं। किसी की मृत्यु या पीड़ा को लोकप्रियता प्राप्त करने का माध्यम बनाना न केवल असंवेदनशीलता का परिचायक है, बल्कि सामाजिक मूल्यों के क्षरण का भी संकेत है।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी ऐसे वीडियो बेहद हानिकारक होते हैं। हिंसक और रक्तरंजित दृश्य देखने से लोगों में तनाव,भय,चिंता और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। कई संवेदनशील व्यक्तियों को लंबे समय तक ऐसे दृश्य परेशान करते रहते हैं। बच्चों और किशोरों पर इसका प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। वे या तो अत्यधिक भयभीत हो सकते हैं या फिर हिंसा को सामान्य व्यवहार के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। इंटरनेट की खुली दुनिया में यह सुनिश्चित करना लगभग असंभव है कि ऐसे वीडियो केवल वयस्कों तक ही सीमित रहें। इसलिए इनका अनियंत्रित प्रसार समाज के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है।

एक और गंभीर समस्या यह है कि लगातार हिंसक सामग्री देखने से लोगों में संवेदनहीनता बढ़ने लगती है। जो दृश्य पहले मन को झकझोर देते थे, वे धीरे-धीरे सामान्य लगने लगते हैं। बार-बार हत्या, दुर्घटना और रक्तपात के दृश्य देखने से मनुष्य के भीतर करुणा और सहानुभूति की भावना कमजोर पड़ सकती है। यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक स्वस्थ समाज की पहचान उसकी संवेदन शीलता होती है। यदि लोग दूसरों के दुःख को महसूस करना छोड़ दें,तो सामाजिक संबंधों और मानवीय मूल्यों की नींव कमजोर होने लगती है।

यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। फेसबुक,इंस्टाग्राम,एक्स, यूट्यूब और अन्य डिजिटल मंचों के पास आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऐसे साधन उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से हिंसक सामग्री की पहचान की जा सकती है। फिर भी अनेक भयावह वीडियो घंटों और कभी-कभी दिनों तक प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं और लाखों लोगों तक पहुँच जाते हैं। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। जिन वीडियो में हत्या, गंभीर हिंसा या बच्चों के विरुद्ध अपराध के दृश्य हों, उन्हें तत्काल हटाया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे कंटेंट को अपलोड और प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।

मीडिया की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता का उद्देश्य केवल दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना नहीं,बल्कि जिम्मेदार तरीके से सूचना देना भी है। वर्षों से पत्रकारिता में कुछ नैतिक मानदंड स्थापित रहे हैं, जिनके तहत मृतकों की गरिमा, पीड़ितों की निजता और दर्शकों की मानसिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इन्हीं मूल्यों का पालन आवश्यक है। किसी घटना के बारे में जानकारी दी जा सकती है, लेकिन उसकी भयावहता को बार-बार प्रदर्शित करना पत्रकारिता नहीं,बल्कि सनसनीखेज प्रस्तुति कहलाएगी। हालाँकि केवल प्लेटफॉर्म्स और मीडिया को दोष देना पर्याप्त नहीं है। दर्शकों और सामान्य नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। किसी भी हिंसक वीडियो को देखने या प्राप्त करने के बाद उसे आगे साझा करना आवश्यक नहीं होता। यदि लोग ऐसे वीडियो को रिपोर्ट करें, उन्हें आगे न बढ़ाएँ और दूसरों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित करें, तो इनके प्रसार को काफी हद तक रोका जा सकता है। डिजिटल नागरिकता का अर्थ केवल इंटरनेट का उपयोग करना नहीं, बल्कि उसका जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना भी है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम तकनीक का उपयोग मानवता को मजबूत करने के लिए करें, न कि पीड़ा को तमाशे में बदलने के लिए। किसी दुखद घटना पर हमारी पहली प्रतिक्रिया संवेदना,सहानुभूति और न्याय की मांग होनी चाहिए, न कि भयावह वीडियो को आगे भेजने की। किसी मासूम बच्चे की हत्या या किसी निर्दोष व्यक्ति की मौत समाज के लिए शोक और आत्ममंथन का विषय है, मनोरंजन या जिज्ञासा का नहीं।

वास्तव में,किसी भी सभ्य और संवेदनशील समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों के प्रति कितना सम्मान और करुणा रखता है। यदि हम किसी की अंतिम पीड़ा को सोशल मीडिया की सामग्री बनाकर प्रसारित करते हैं,तो हम केवल एक वीडियो साझा नहीं कर रहे होते,बल्कि अपनी संवेदनशीलता का भी एक हिस्सा खो रहे होते हैं। इसलिए समय की मांग है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसी सामग्री को तुरंत हटाएँ, कानून अपना कार्य करे और समाज स्वयं भी यह संकल्प ले कि किसी की त्रासदी को वायरल नहीं,बल्कि मानवता और संवेदना को वायरल करना है। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी नैतिक आवश्यकता है।

अहंकार आतंक,सत्ता और युद्ध का कारण

संजय गोस्वामी,मुंबई,महाराष्ट्र

अहंकार और लोभ ही युद्ध को आग में घी डालने का काम करता है राम ने शान्ति स्थापना के लिए युद्ध किया लेकिन आज जो युद्ध ईरान और यूक्रेन पर अमेरिका - इजराइल और रूस द्वारा हो रहा वहाँ अहंकार और लोभ हीमुख्य कारण दिखता है जहाँ तक इजराइल के बेरूत पर हमले की बात है ऐ उसका अंदुरुनी मामला है और जहाँ तक इजराइल की बात है वो अमेरिका के हथियार के द्वारा ही हमला कर रहा है एक बात सोचना सभी राष्ट्र को जरुरी है अपने यहाँ कभी आतंकवाद को पाले नहीं युद्ध आतंकवादी के पालने पोसने से होता है आतंकवादी जिस तरह लोगों निर्दोष नागरिक की हत्या करते हैं वो क्या सही है पाकिस्तान हमेशा भारत को आतंकी भेज कर निर्दोष नागरिक की हत्या करवाता रहता है पहले सरकार कोई और थी अब बदल गई है ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के गढ़ में जाकर आतंकी शिविर को नष्ट किया तब से अपने आप शांत हो गया मैं भारत का हूँ इसलिए भारत माता के बारे में ही मर मिटने का जूनून है और जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए है इजराइल देश ने मदद की है इसलिए इजराइल हमारा मित्र देश है कई सैन्य अभ्यास होते हैं आज ईरान के चुने हुए राष्ट्रपति आईआरजीको इस्तीफा क्यों दिया क्योंकि वहाँ प्रशासन की कोई सुन नहीं रहा है.

भगवान राम को किसी बात का अहंकार नहीं था। श्रीराम तो सर्वज्ञ थे,किन्तु रावण को ज्ञान के साथ-साथ शक्ति और और सत्ता का अहंकार था अविनम्र आदमी ही अहंकारी होता है,विनम्र आदमी नहीं वस्तुतः जिस आदमी का अहंकार आ गया वो क्रोध लोभ मोह से घिर जाता है। जिसका सत्ता का अहंकार हो गया वह सत्ता मात्र एक समय के लिए होता है।लेकिन सत्ता को बनाये रखने के लिए युद्ध तक करता है क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि सत्ता जो मिली है आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगा

अहंकार पर आपकी चोट एकदम सटीक है। वेदांत का पहला और आखिरी पुरुषार्थ अहं-वृत्ति को साक्षी-भाव से देखना ही है। मृत्यु, भोग, सोशल मीडिया का भ्रम—ये सब अहंकार के ही खेल हैं। काल का स्मरण कराना और युवाओं को भोग से परे देखने को कहना, यह ऋषि-परंपरा है। पर वेदांत सब अहंकार ही है कहकर रुकता नहीं। वो कहता है—अहंकार मिथ्या है, पर उसका आधार ब्रह्म सत्य है। शास्त्र को फेंक नहीं देते,नाव की तरह पार उतरकर छोड़ते हैं। ब्रह्म को शक्तिहीन अनजान कहना स्वयं अहंकार की भाषा है, क्योंकि ब्रह्म न शक्त है न अशक्त – वह शक्ति का अधिष्ठान है। आत्मा-परमात्मा घटित नहीं होते, वे नित्य-सिद्ध हैं; सिर्फ अहंकार का पर्दा हटता है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ हि=कारण कि, जातस्य=पैदा हुएकी, ध्रुवः = जरूर,मृत्युः = मृत्यु होगी,च =और,मृतस्य=मरे हुएका, ध्रुवम् = जरूर,जन्म = जन्म होगा,तस्मात्=अतः, (इस जन्म-मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का) निवारण नहीं हो सकता,अर्थे=(अतः) इस विषयमें,त्वम्=तुम्हें, शोचितुम् =शोक,न =नहीं,अर्हसि = करना चाहिये। व्याख्या-जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवं जन्म मृतस्य च%-पूर्वश्लोकके अनुसार अगर शरीरीको नित्य जन्मने और मरनेवाला भी मान लिया जाय,तो भी वह शोकका विषय नहीं हो सकता। कारण कि जिसका जन्म हो गया है,वह जरूर मरेगा और जो मर गया है, वह जरूर जन्मेगा। न त्वं तस्मादपरिहार्येऽर्थे शोचितुमर्हसि-इसलिये कोई भी इस जन्म-मृत्युरूप प्रवाहका परिहार (निवारण) नहीं कर सकता;क्योंकि इसमें किसीका किंचिन्मात्र भी वश नहीं चलता। यह जन्म-मृत्युरूप प्रवाह तो अनादिकालसे चला आ रहा है और अनन्तकालतक चलता रहेगा। इस दृष्टि से तुम्हारे लिये शोक करना उचित नहीं है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जन्में हैं, तो जरूर मरेंगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे तुम उनको बचा सको। जो मर जायँगे, वे जरूर जन्मेंगे। उनको भी तुम रोक नहीं सकते। फिर शोक किस बातका ? शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय। अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय ॥ जैसे,इस बातको सब जानते हैं कि सूर्यका उदय हुआ है,तो उसका अस्त होगा ही और अस्त होगा तो उसका उदय होगा ही। इसलिये मनुष्य सूर्यका अस्त होनेपर शोक-चिन्ता नहीं करते। ऐसे ही हे अर्जुन ! अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीरके साथ ये भीष्म,द्रोण आदि सभी मर जायँगे, तो फिर शरीरके साथ जन्म भी जायँगे। अतः इस दृष्टिसे भी शोक नहीं हो सकता। भगवान् राम ने इन दो (छब्बीसवें-सत्ताईसवें) श्लोकोंमें जो बात कही है,वह भगवान् का कोई वास्तविक सिद्धान्त नहीं है।

लघुकथा

अपने ही...

टीकेश्वर सिन्हा
गब्दीवाला
बालोद,छत्तीसगढ़

बयासी का अशोक और अस्सी की उम्र वाली वसुधा दोनों रिक्शे पर बैठे थे। वसुधा को पता तक नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। पति अशोक की तर आँखों को देख वसुधा ने पूछा...आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं ? कुछ तो बोलो... और ये आँसू...?

अशोक :-चुप बैठी रहो न वसु। जान जाओगी भाई। लो, मैंने पोंछ लिया अपने आँसू।

वसुधा : - तो बताने में क्या हर्ज है जी। अभी तक तो तुमने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई।

अशोक : -दरअसल हमने अपना वसुधा सदन छोड़ दिया है। अब हम कहीं और जगह रहेंगे।

वसुधा : - पर रो क्यों रहे हो ? और क्यों छोड़ना पड़ रहा है हमें अपना घर...कहाँ रहेंगे ?

दोनों बतिया ही रहे थे कि अचानक रिक्शा रूका। अशोक व वसुधा दोनों उतरे। तभी वसुधा की नजर पड़ी एक बोर्ड पर। लिखा था- ओल्ड एज होम। वसुधा अशोक के सीने से लग गयी। उसे सब समझ आ गया।

रिक्शा मोड़ते हुए रिक्शेवाले से अशोक ने पूछा- कितना लगेगा भाई...?

रिक्शावाला :- मेरो को मिल गया है भाड़ा। आपके बड़े बेटे ने दे दिया है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

विधायक-नायब तहसीलदार विवाद ने पकड़ा तूल,दो समर्थकों ने किया सरेंडर

एसडीएम और नायब तहसीलदार को हटाने की मांग तेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026
(घटती-घटना)।
सीतापुर के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट मामले में दर्ज एफआईआर के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामले में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के दो समर्थकों ने बुधवार को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। वहीं दूसरी ओर विधायक समर्थक संगठनों ने एसडीएम और नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई तथा विधायक पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग तेज कर दी है। गौरतलब है कि नायब तहसीलदार तुषार मानिक की रिपोर्ट पर विधायक रामकुमार टोप्पो सहित उनके 10 समर्थकों के खिलाफ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारी गिरफ्तारी की मांग को लेकर तीन दिन से हड़ताल पर हैं।मामले में नामजद दो आरोपियों ग्राम कोटछाल निवासी पंकज गुप्ता (30) और ग्राम पेट निवासी नाजिम रजा (34) ने बुधवार को सीतापुर थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों का नाम एफआईआर में शामिल है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार दोनों ने विधायक के निर्देश पर सरेंडर किया है। विवाद के बीच यह चर्चा भी तेज है कि विधायक पक्ष द्वारा राजापुर के एसडीएम फागेश सिन्हा और नायब तहसीलदार तुषार मानिक को सीतापुर से हटाने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में वरिष्ठ भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हुई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है।

राजस्व कामकाज प्रभावित,कलेक्टर ने लौटने कहा...

इधर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से आम नागरिकों के कार्य प्रभावित होने लगे हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से काम पर लौटने की अपील की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में कार्य पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

मितानिनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन...

सीतापुर विधायक की बहन सीमा धनकी के समर्थन में जिलेभर की मितानिनें भी मैदान में उतर आई हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में मितानिनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नायब तहसीलदार पर विधायक की बहन से कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की। साथ ही मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से भी की गई है। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है।

सर्व आदिवासी समाज भी आया समर्थन में...

सर्व आदिवासी समाज ने भी विधायक रामकुमार टोप्पो के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक क्षेत्र में सक्रियता से विकास कार्य कर रहे हैं। उनका सैन्य सेवा का भी गौरवशाली रिकॉर्ड रहा है तथा उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका है। ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाना उचित नहीं है। समाज ने तीन दिन के भीतर नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

छात्र संगठन भी उतरा मैदान में...

विधायक के समर्थन में अब छात्र संगठन भी सामने आ गया है। संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की है। एक ओर जहां भाजपा समर्थक, छात्र संगठन, मितानिनें और सर्व आदिवासी समाज विधायक के समर्थन में खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेशभर का राजस्व अमला नायब तहसीलदार के पक्ष में आंदोलनरत है।

बढ़ता जा रहा है टकराव

राजस्व अधिकारियों की हड़ताल, समर्थक संगठनों के प्रदर्शन और प्रशासनिक कार्रवाई की मांगों के बीच यह मामला अब केवल मारपीट की घटना तक सीमित नहीं रह गया है। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर बढ़ते दबाव के कारण पूरे प्रदेश की नजरें अब इस मामले में प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

करोड़ों की लोन ठगी मामले में थाने के बाहर हंगामा,शिक्षकों ने आरोपियों के रिश्तेदारों से की मारपीट

शिक्षकों के नाम पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप,मामले की जांच में जुटी पुलिस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग में शिक्षकों के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित लोन ठगी का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को गांधी नगर थाना परिसर के बाहर जमकर हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार, शिक्षकों के नाम पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपये की ठगी किए जाने का आरोप है। इस मामले में गांधी नगर पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी के कुछ रिश्तेदार थाना पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मौजूद शिक्षकों और रिश्तेदारों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और शिक्षकों ने कथित तौर पर रिश्तेदारों के साथ मारपीट कर दी। घटना से थाना परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल गांधी नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, सरगुजा : सेवा, सुशासन एवं पर्यावरण संरक्षण पर जोर...जिला कार्यसमिति की बैठक सम्पन्न

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों को गति देने की रूपरेखा तय

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026
(घटती-घटना)।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला कार्यसमिति की बैठक आज संकल्प भवन, भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी,संगठन सरगुजा संभाग प्रभारी अवधेश सिंह चंदेल,भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया,अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष शिव शंकर सिंह मरावी, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिला महामंत्री विनोद हर्ष, महामंत्री द्वय श्रीमती अरुणा सिंह, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष बिंदेश्वरी लाल पैकरा सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रविकांत ओराँव ने किया तथा आभार प्रेषण कमलेश टोप्पो ने व्यक्त किया। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि यह समय सेवा और संकल्प का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाई जा रही जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर पहुंचाकर हर नागरिक का जीवन स्तर उन्नत करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। इस अवसर पर संगठन सरगुजा संभाग प्रभारी अवधेश सिंह चंदेल ने कहा कि संगठनात्मक मजबूती के साथ जनसंपर्क ही असली शक्ति है। कार्यकर्ताओं को मैदान में सक्रिय कर योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनहित और विकास की भावनाओं को जन-जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। वार्षिक योजनाओं तथा पर्यावरणीय पहलों में जनता का समन्वय आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयास जारी रहेंगे। उनकी सहभागिता से विकास और समावेशन दोनों सुनिश्चित होंगे। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि स्थानीय शासन व समाज के बीच तालमेल बढ़ाकर स्वच्छता और हरित परियोजनाओं को सफल बनाना हमारा लक्ष्य है। जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने कहा कि कार्यक्रमों की प्रभावी रूपरेखा और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए पूरी टीम तत्पर रहेगी। महामंत्री द्वय अरुणा सिंह ने कहा कि महिलाओं और परिवारों तक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विशेष रूप से पहुंचाने पर जोर रहेगा। रविकांत ओराँव बैठक का संचालन करते हुए उन्होंने आवश्यक विषयों पर सुव्यवस्थित चर्चा और निर्णय सुनिश्चित किए तथा कमलेश टोप्पो द्वारा बैठक के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने सभी उपस्थित अतिथियों व कार्यकर्ताओं को आगामी अभियानों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में एसटी मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे ।

सरगुजा जिले में 14 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की आमद डीआईजी/एसएसपी ने दिया आवश्यक दिशा-निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026
(घटती-घटना)।
पुलिस मुख्यालय रायपुर के आदेशानुसार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राज्य पुलिस अकादमी से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त 14 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सरगुजा जिले में पदस्थ किया गया है। प्रशिक्षुओं की आमद के उपरांत राजेश अग्रवाल ने बैठक लेकर उन्हें कर्तव्य निर्वहन, निष्पक्ष जांच-विवेचना एवं तकनीकी दक्षता से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक के दौरान डीआईजी/एसएसपी श्री अग्रवाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पर अनुशासन, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा में निष्पक्षता, संवेदनशीलता और तकनीकी ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान सौंपे गए प्रत्येक दायित्व को गंभीरता, लगन और मेहनत से पूरा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस मुख्यालय द्वारा आवंटित इन 14 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को जिले के विभिन्न थानों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थ किया गया है। इसके तहत थाना कोतवाली अंबिकापुर में तीन, थाना गांधीनगर, सीतापुर एवं मणिपुर में दो-दो तथा उदयपुर, लखनपुर, बतौली, लुंड्रा एवं दरिमा में एक-एक प्रशिक्षु उपनिरीक्षक की पदस्थापना की गई है। बैठक में राहुल बंसल,रक्षित निरीक्षक तृप्ति सिंह राजपूत,उपनिरीक्षक (एम) अभय सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को जमीनी स्तर पर पुलिस कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था प्रबंधन, अपराध अनुसंधान एवं जनसंपर्क से संबंधित व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है, जिससे वे भविष्य में अधिक दक्ष एवं प्रभावी पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।

सत्तादल-प्रशासन टकराव को लेकर कांग्रेस का राज्यपाल के नाम ज्ञापन,राष्ट्रपति शासन की मांग...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026
(घटती-घटना)।
सीतापुर विधायक एवं राजस्व विभाग के एक अधिकारी के बीच हुए विवाद और उसके बाद प्रदेशभर में राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में उत्पन्न स्थिति पर चिंता जताई है। कांग्रेस ने आमजन को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर प्रशासनिक तंत्र को संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया है।जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक द्वारा राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक राजस्व अधिकारी के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, विलंबित जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अनेक राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है,जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है। कांग्रेस ने इसे गंभीर प्रशासनिक संकट बताते हुए कहा है कि ऐसी परिस्थितियां प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती हैं।

कांग्रेस ने राज्यपाल से दो प्रमुख मांगें की हैं। पहली, राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप कर उन्हें शीघ्र कार्य पर लौटाने की व्यवस्था की जाए,ताकि आम जनता को राहत मिल सके। दूसरी,प्रदेश में उत्पन्न हालात का परीक्षण कर केंद्र सरकार को प्रतिवेदन भेजते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाए।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी पांच दिनों के भीतर मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस पार्टी जनहित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हालांकि, प्रदेश सरकार या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कांग्रेस के आरोपों और मांगों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

जूनियर नेशनल किकबॉक्सिंग में सरगुजा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन..शौर्यवर्धन और संगीता ने जीते रजत पदक, जिले का बढ़ाया मान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।
भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप-2026 में सरगुजा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से सरगुजा के पांच खिलाड़ियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग के 51 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए शौर्यवर्धन सिंह ने शानदार प्रदर्शन कर रजत पदक अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में संगीता सिंह ने भी दमदार खेल दिखाते हुए रजत पदक हासिल किया। चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से कुल 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सरगुजा के दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों,साथी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और परिजनों में खुशी का माहौल है। खिलाड़ियों की सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है। जिले के खेल जगत से जुड़े लोगों ने कहा कि यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है और इससे सरगुजा में किकबॉक्सिंग खेल को नई पहचान मिलेगी।

शिक्षा के मंदिर में चिकन पार्टी! सुशासन तिहार के दौरान सरकारी परिसरों में दावत पर उठे सवाल

आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल परिसर में अधिकारियों-कर्मचारियों की पार्टी का वीडियो-फोटो वायरल,आम लोगों की शिकायतों के बीच मौज-मस्ती के आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026
(घटती-घटना)।
प्रदेश सरकार के सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अंबिकापुर क्षेत्र के एक आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल परिसर में कथित तौर पर चिकन पार्टी आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर के साड़बार स्थित आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा चिकन पार्टी आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। वहीं हर्राटिकरा क्षेत्र के एक स्कूल परिसर में भी इसी तरह के आयोजन की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक ओर सुशासन तिहार के तहत आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी सरकारी परिसरों में पार्टी और पिकनिक का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इससे शासन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।

सिघत में विकास की राशि पर डाका या व्यवस्था की मेहरबानी?

15वें वित्त आयोग की रकम फर्जी बिलों के सहारे हजम करने का आरोप, हैंडपंप मरम्मत में 40 हजार का खेल चर्चा में...

ग्रामीणों का सवाल...काम जमीन पर नहीं...भुगतान कागजों पर कैसे हो गया?

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,03 जून 2026 (घटती-घटना)। गांवों के विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है। पंचायतों को वित्त आयोग की राशि इसलिए दी जाती है ताकि पेयजल, सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन जब विकास की रकम विकास पर कम और कागजों पर ज्यादा दिखाई देने लगे, तब सवाल केवल एक पंचायत का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का बन जाता है। खड़गवां जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिघत इन दिनों ऐसे ही आरोपों को लेकर चर्चा में है, आरोप है कि पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग विकास कार्यों में कम और फर्जी बिलों के सहारे भुगतान निकालने में अधिक किया गया। ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कई ऐसे कार्यों का भुगतान कर दिया गया जिनका वास्तविक स्वरूप जमीन पर दिखाई नहीं देता।

हैंडपंप मरम्मत में 40 हजार का भुगतान,ग्रामीणों ने उठाए सवाल

सबसे ज्यादा चर्चा एक हैंडपंप मरम्मत कार्य को लेकर है,आरोप है कि मरम्मत के नाम पर लगभग 40 हजार रुपये की राशि खर्च दिखा दी गई, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर ऐसा कोई बड़ा कार्य दिखाई नहीं देता जिससे इतनी बड़ी राशि खर्च होने का औचित्य साबित हो सके, गांव के लोगों का सवाल है कि यदि वास्तव में मरम्मत कार्य हुआ था तो उसका तकनीकी परीक्षण कराया जाए और यह बताया जाए कि आखिर कौन-कौन से कार्य किए गए जिन पर इतनी राशि खर्च हुई।

पुराने काम को नया बताकर निकाली गई राशि?

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तत्कालीन सरपंच कार्यकाल में स्थापित सबमर्सिबल पंप, सिंटेक्स और पेयजल स्त्रोतों से जुड़े कार्यों को वर्तमान कार्य बताकर भुगतान निकाला गया, ग्रामीणों का कहना है कि जिन कार्यों को आधार बनाकर राशि निकाली गई, उनमें से कई कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे, इसके बावजूद नए कार्यों के नाम पर भुगतान होना कई सवाल खड़े करता है,यदि आरोप सही हैं तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला माना जाएगा।

फर्जी बिलों का खेल या विकास का मॉडल?

सिघत पंचायत को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि कई भुगतान बोगस या संदिग्ध बिलों के आधार पर किए गए,ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में विकास कार्यों का वास्तविक मूल्यांकन किया जाए तो कई भुगतान और मौके की स्थिति में भारी अंतर दिखाई देगा, व्यंग्य में गांव के लोग कहते हैं कि यहां विकास पहले कागजों में होता है और बाद में अगर समय मिला तो जमीन पर उतरता है।

जनपद अधिकारियों की चुप्पी पर भी सवाल-मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि शिकायतें और समाचार सामने आने के बावजूद अब तक किसी ठोस जांच की जानकारी सामने नहीं आई है, यही वजह है कि ग्रामीण अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पंचायत स्तर के भ्रष्टाचार को जनपद स्तर का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि सामान्य धारणा यह है कि पंचायतों के वित्तीय मामलों की निगरानी जनपद पंचायत के माध्यम से होती है, ऐसे में यदि लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

'प्रसाद' पहुंच गया तो जांच का डर कैसा?- ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यंग्यात्मक चर्चा अक्सर सुनाई देती है कि यदि ऊपर तक 'प्रसाद' पहुंच जाए तो फिर जांच की फाइलें भी आराम करने लगती हैं, सिघत पंचायत को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि शिकायतें निराधार हैं तो जांच कर पंचायत को क्लीन चिट दे दी जाए और यदि शिकायतों में दम है तो दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन न जांच पूरी हो रही है और न जवाब सामने आ रहा है।

15 वें वित्त आयोग का उद्देश्य क्या था?- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम और वित्त आयोग की अनुशंसाओं का मूल उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिल सके, इस राशि से पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाएं और अन्य मूलभूत कार्य किए जाने हैं, लेकिन यदि यही राशि फर्जी बिलों और संदिग्ध भुगतानों में खर्च होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीणों को ही होता है,जिन्हें विकास का लाभ मिलना चाहिए था।

पहले भी उठ चुके हैं सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि यह पहला मामला नहीं है, पंचायत में पहले भी निर्माण कार्यों, जीर्णोद्धार और पेयजल योजनाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगाए जाते रहे हैं कि कई कार्य कागजों में पूरे दिखाए गए लेकिन मौके पर उनका स्पष्ट अस्तित्व नहीं मिला, यही कारण है कि अब पंचायत के वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच की मांग जोर पकड़ रही है।

अब ग्रामीण कर सकते हैं उच्चस्तरीय शिकायत

मामले को लेकर ग्रामीणों के बीच नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है,गांव में चर्चा है कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होती तो शिकायत जिला पंचायत,कलेक्टर और अन्य उच्च स्तरीय एजेंसियों तक पहुंचाई जाएगी, ग्रामीणों का कहना है कि जांच केवल कागजों की नहीं बल्कि मौके की होनी चाहिए,भुगतान,माप पुस्तिका, बिल,वाउचर और कार्यस्थल का भौतिक सत्यापन कराया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

सबसे बड़ा सवाल- सिघत पंचायत में आखिर हुआ क्या?

क्या वास्तव में विकास कार्य हुए और शिकायतें राजनीतिक हैं? या फिर विकास के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट हुआ? इन सवालों का जवाब केवल निष्पक्ष जांच ही दे सकती है, फिलहाल गांव में एक ही चर्चा है विकास जमीन पर हुआ या सिर्फ फाइलों में? और यदि पैसा खर्च हुआ तो उसका लाभ आखिर किसे मिला?

(नोटः समाचार में वर्णित आरोप शिकायतकर्ताओं और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित हैं,संबंधित सरपंच,सचिव और जनपद अधिकारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)

236 हितग्राहियों को लॉटरी से हुआ मकानों का आबंटन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

नगर पालिक निगम अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत सुभाषनगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 'मोर मकान - मोर आस' परियोजना में 236 हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से मकानों का आबंटन किया गया। आयुक्त श्री डी.एन. कश्यप के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में यह आबंटन प्रक्रिया माता राजमोहिनी भवन में पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत मोर मकान-मोर आस में शासन से स्वीकृत कुल 493 आवासों हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच एवं भौतिक सत्यापन उपरांत पात्र हितग्राहियों को अंतिम चरण में शेष 236 आवासों का आबंटन लॉटरी पद्धति के द्वारा किया गया। शेष आवासों का आबंटन पूर्व में किया जा चुका है। इस अवसर पर सभापति श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी, नोडल अधिकारी श्री राजेश राम, परियोजना के सहायक अभियंता श्री दुष्यंत बजाज, सहायक नोडल श्री प्रेमप्रकाश दुबे, सीएलटीसी सुश्री जगदम्बा त्रिवेदी, श्री अनिकेत गोस्वामी, श्री उत्कर्ष पाण्डे, कार्यालय अधीक्षक श्री दीपक वर्मा, स्थानीय जनप्रतिनिधि,नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे।

जन समस्या निवारण शिविर में मंत्री राजेश अग्रवाल हुए शामिल

जनता से सीधा संवाद कर सुनीं मांग एवं समस्याएं....

अधिकारियों को दिए गुणवत्ता पूर्ण समय पर निराकरण करने के निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी पहल 'सुशासन तिहार 2026' के अंतर्गत प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से अंबिकापुर जनपद पंचायत के ग्राम हर्रा टिकरा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस समाधान शिविर में क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली 27 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भारी संख्या में भाग लिया तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में कुल 1,153 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,106 मांग संबंधी एवं 47 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। समाधान शिविर में 22 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया, जबकि शेष 1131 आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। इन सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

समाधान शिविर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। स्टॉल के माध्यम से ग्रामीणों को हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जनता से सीधा संवाद कर उनकी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को सुनीं और अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने निर्देश दिए। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशन में सुशासन तिहार कार्यक्रम का यह महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें जनप्रतिनिधि सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी एक स्थल पर उपस्थित होकर आप सबकी विभिन्न मांग एवं समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करते है। स्थानीय स्तर पर निराकरण योग्य आवेदक को निराकरण किया जा रहा है। पेंशन, राशन कार्ड, फौती नामांतरण, सीमांकन एवं आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निराकरण किए जाएंगे। उन्होंने ग्रामीण जनों से कहा कि मांग एवं समस्याओं का जानकारी दें जिसका निराकरण किया जाएगा। शासन के द्वारा आम जनता की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत बिजली बिल समस्या का समाधान किया जा रहा है आज तक 69 हजार अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है शेष है उनका भी निराकरण किया जाएगा आवेदन करें। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि स्कूल, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष कार्य किया जा रहा है जिले में स्कूल के अतिरिक्त भवन एवं मरम्मत कार्य के लिए 59 स्कूलों को चिन्हित कर कार्य किया जा रहा है जिससे बच्चों को सुविधायुक्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

तहसील सीतापुर क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन करते 09 वाहन जप्त

-संवाददाता-
सीतापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन,परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। खनि अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 जून 2026 को खनिज अमला द्वारा सीतापुर तहसील अतर्गत ग्राम केसला घाट, मंगरे लगढ़,बिठुआ,लमगांव,ढेलसरा, राधापुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र में खनिज परिवहन करते वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान नीला स्वराज सोल्ड ट्रैक्टर वाहन चालक राकेश कुमार सतनामी वाहन मालिक इमामुदिन खान,CG 15 AE 3770 वाहन चालक मालिक खिलावन,CG 14 E 1555 वाहन चालक अमन खलखो वाहन मालिक विजय कुमार, CG 15 DU 9515 वाहन चालक असीम वाहन मालिक गुड्डू तिग्गा, महेन्द्रा सोल्ड ट्रैक्टर लाल वाहन चालक उमीद कुमार वाहन मालिक कन्हैयालाला यादव, मैसी 246 सोल्ड ट्रैक्टर लाल वाहन चालक मालिक कोमल सिंह, मैसी 5245 सोल्ड ट्रैक्टर लाल वाहन चालक पुष्प राज सिंह वाहन मालिक जगेश्वर सिंह, महेन्द्रा लाल सोल्ड ट्रैक्टर वाहन चालक रिपेल माझी वाहन मालिक आशीष खेस, जॉन डीयर ट्रेक्टर सोल्ड वाहन चालक प्रदीप मिंज वाहन मालिक नईम अंसारी द्वारा बिना अभिवहन पास खनिजों का परिवहन करते पाए गए। वाहनों पर अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर थाना सीतापुर की अभिरक्षा में अग्रिम आदेश तक रखा गया। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) एवं एमएमडीआर की धारा 21 (5) एवं 23 के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर विभाग की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

अवैध प्रविष्टी करने पर प्रभारी सहायक मलेरिया अधिकारी पर कार्रवाई के कलेक्टर ने दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट राजेश गुप्ता के विरुद्ध शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ एवं नियम विरुद्ध पदोन्नति प्राप्त करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि राजेश गुप्ता, जो पूर्व में सहायक मलेरिया अधिकारी के प्रभार में कार्यालय में पदस्थ थे। इनसे सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय से चाही गयी थी। किन्तु जिला मलेरिया अधिकारी के प्रभार में रहने के कारण राजेश गुप्ता के द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध न कराते हुए स्वयं अपने शासकीय रिकार्ड में अनाधिकृत रूप से रखा गया है। उक्त सेवा पुस्तिका में आवश्यक शासकीय एवं पदीय संबधित पारित आदेश दर्ज किया जाता है। सबंधित के विरूद्ध शासकीय सेवा से सबंधित अनियमितता संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने बताया कि सेवा पुस्तिका एक महत्वपूर्ण शासकीय अभिलेख है जिसका संधारण कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। किसी भी कर्मचारी द्वारा इसे अपने पास रखना गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। किसी शासकीय अभिलेख के साथ कुटरचना अथवा नष्ट किया जा सकता है। कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है, कि सम्बंधित के द्वारा सेवा पुस्तिका में अपने मन मर्जी वार्षिक वेतनवृद्धि, समायोजन का इंद्राज कर भ्रम की स्थिति निर्मित कर शासकीय कार्य बाधित किया जा रहा है। कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये सरगुजा संभाग के एक आदेशानुसार राजेश गुप्ता का समायोजन मेडिकल लैब टैक्नालाजिस्ट से सहायक मलेरिया अधिकारी अम्बिकापुर में लेवल 9 (वेतन मान 9300-34800, ग्रेड वेतन 4300) में किया गया है। जो नियम विरूद्ध एवं वैधानिक नहीं है। विभागीय भर्ती ध् पदोन्नति नियम 2013 के तहत सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर पदोन्नती हेतु सक्षम अधिकारी संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये है। मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट पद से पदोन्नती जीव विज्ञान रसायन बायोकेमिस्ट निर्धारित है। सहायक मलेरिया अधिकारी के पदोन्नति पद हेतु उपयुक्त कैडर है, मलेरिया निरीक्षक ध् स्वास्थ्य शिक्षक (हेल्थ एजुकेटर/गैर चिकित्सकीय पर्यवेक्षक) को निधारित किया गया है, आवश्यक योग्यता 5 वर्ष का सेवा अनुभव निर्धारित है। बिना विभागीय डी.पी.सी एवं वरिष्ठता सूची जारी किए सहायक मलेरिया अधिकारी के पद पर समायोजित किया जाना नियमों के विपरीत है एवं वैधानिक नहीं है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अनुपस्थित कर्मचारियों को नोटिस देने दिया निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.पी.एस.मार्को ने बुधवार को विकासखंड उदयपुर अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलका एवं उप स्वास्थ्य केंद्र सोनतराई का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलका में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने निर्देश दिए। उन्होंने एपीवी वैक्सीनेशन कार्य,लंबित आयुष्मान कार्ड निर्माण,आधार आधारित उपस्थिति दर्ज कराने तथा निर्धारित समय पर सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाइयों के पर्याप्त भंडारण की जानकारी ली तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी एवं सिकल सेल मरीजों की जांच संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी एवं सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने तथा मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान तीन कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए।

अंबिकापुर में युवक-युवती की फांसी पर लटकी मिली लाश,क्षेत्र में सनसनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के बेलसरापारा गांव में एक युवक और युवती की फांसी पर लटकी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने गांव के पास एक आम के पेड़ पर दोनों के शव फांसी के फंदे से लटके देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय किशोर राम पिता रवि राम निवासी बेलसरापारा और 20 वर्षीय डोंगाली राम पिता बुनूराम निवासी झुमापारा, बाघमुंडा (उदयपुर) के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही उदयपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार किशोर राम 2 जून की रात करीब 10 बजे घर से निकला था।

इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने उसका शव पेड़ पर लटका देखा। वहीं पास में युवती का शव भी फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के बीच युवक और युवती के प्रेम संबंध होने की चर्चा है। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने एक साथ आत्मघाती कदम उठाया हो, हालांकि पुलिस ने अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जांच के दौरान सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की। इसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। उदयपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है तथा घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है। इस दुखद घटना के बाद गांव में शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

मनरेगा में महक रहा है 'चंदन',भुगतान की फाइलों पर पहले खुशबू फिर दस्तखत!

मनरेगा में चंदन की खुशबू या कमीशन का कमाल? बैकुंठपुर जनपद में भुगतान पर उठे बड़े सवाल

-रवि सिंह-
कोरिया,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

मनरेगा का उद्देश्य गांवों में रोजगार देना,मजदूरों को समय पर भुगतान करना और विकास कार्यों को गति देना है,लेकिन बैकुंठपुर जनपद पंचायत में इन दिनों मनरेगा की चर्चा कम और चंदन की खुशबू की चर्चा ज्यादा हो रही है, यह खुशबू किसी इत्र की नहीं है,बल्कि पंचायतों में चल रही उन चर्चाओं की है जिनमें कहा जा रहा है कि यहां फाइलें नियमों से कम और संबंधों से ज्यादा चलती हैं।

जनपद पंचायत के गलियारों में बैठे-बैठे लोग मजाक में कहते हैं कि बैकुंठपुर में मनरेगा की फाइलों का अपना मौसम है,बरसात,गर्मी और ठंड के अलावा यहां एक चौथा मौसम भी चलता है–एफटीओ व एमआईएस सीजन। इस मौसम में पंचायतों के सचिव,सरपंच, रोजगार सहायक और ठेकेदार जैसे लोग जनपद कार्यालय की परिक्रमा करते नजर आते हैं,कोई मजदूरों का भुगतान निकलवाने आया है, कोई निर्माण कार्य का बिल अटका हुआ है,तो कोई महीनों से सिस्टम में फंसी फाइल को ढूंढ रहा है, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है, वह है सहायक प्रोग्रामर चंदन सिंह।

मनरेगा का डिजिटल दरबार और उसके कथित दरबान

कहने को मनरेगा एक ऑनलाइन व्यवस्था है,भुगतान प्रक्रिया डिजिटल है,फाइलें पोर्टल पर चलती हैं, अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं, सब कुछ पारदर्शी बताया जाता है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि बैकुंठपुर में डिजिटल सिस्टम का भी एक दरबार है और उस दरबार का एक कथित दरबान है, जिसके बिना फाइलों की यात्रा अधूरी मानी जाती है, बताया जाता है कि 120 से अधिक पंचायतों से आने वाली फाइलों की अंतिम मंजिल वही टेबल होती है जहां से एफटीओ और एमआईएस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसकी चर्चा पंचायत से लेकर चाय की दुकानों तक हो रही है वो भी जनपद कार्यालय के सामने वाले चाय की दुकानों।

नियमों की किताबः गरीब की फाइल में मोटी, अमीर की फाइल में पतली!

पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सबसे लोकप्रिय चर्चा यह है कि जनपद कार्यालय में एक अदृश्य नियमों की किताब रखी हुई है,जब कोई पंचायत भुगतान के लिए फाइल लेकर पहुंचती है और व्यवस्था नहीं बन पाती,तब वही किताब अचानक खुल जाती है,फिर उसमें से नए-नए नियम निकलते हैं, कहीं हस्ताक्षर कम हैं,कहीं फोटो स्पष्ट नहीं है,कहीं मस्टर रोल में कमी है,कहीं तकनीकी स्वीकृति का सवाल खड़ा हो जाता है,फाइल वापस,भुगतान लंबित,मजदूर परेशान,सरपंच परेशान,सचिव परेशान लेकिन आरोप लगाने वालों का दावा है कि जैसे ही व्यवस्था बन जाती है,वही किताब चमत्कारिक रूप से बंद हो जाती है, जो कमी कल तक पहाड़ लग रही थी,वह आज राई बन जाती है, जो दस्तावेज कल अधूरे थे, वे अचानक पूर्ण घोषित हो जाते हैं, और फिर भुगतान की गाड़ी ऐसी दौड़ती है जैसे उसे कभी ब्रेक लगाया ही न गया हो।

मजदूर इंतजार में, फाइलें कतार में और भुगतान 'प्राथमिकता' में...

मनरेगा की आत्मा मजदूर है,योजना का मूल उद्देश्य मजदूरों को समय पर मजदूरी देना है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि कई बार मजदूरों का भुगतान सप्ताहों और महीनों तक अटका रहता है,मजदूर सरपंच से पूछता है,सरपंच सचिव से पूछता है, सचिव जनपद से पूछता है,और जनपद में जवाब मिलता है प्रक्रिया चल रही है,यह प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि मजदूर को लगता है शायद उसकी मजदूरी दिल्ली से पैदल चलकर आ रही है।

जांच हुई तो कई परतें खुल सकती हैं...

बैकुंठपुर जनपद में चल रही चर्चाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इन शिकायतों की गंभीर जांच करेगा? क्या यह देखा जाएगा कि किन पंचायतों के भुगतान समय पर हुए और किनके महीनों तक लंबित रहे? क्या एफटीओ और एमआईएस की प्रक्रिया का ऑडिट होगा? क्या यह पता लगाया जाएगा कि भुगतान में देरी के वास्तविक कारण क्या थे? और सबसे महत्वपूर्ण,क्या मजदूरों और पंचायतों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में सुधार होगा? क्योंकि आखिरकार मनरेगा का पैसा किसी अधिकारी,कर्मचारी या सिस्टम का नहीं,बल्कि गांव के उस मजदूर का है जो शाम को घर लौटते समय अपने बच्चों के लिए राशन खरीदने की उम्मीद करता है,और जब मजदूर की मजदूरी फाइलों में फंस जाती है,तब सबसे ज्यादा जरूरत नियमों की किताब खोलने की नहीं,बल्कि जवाबदेही की किताब खोलने की होती है।

सीईओ से शिकायत कर दी? फिर फोन क्यों किया!

इस पूरे मामले में सबसे रोचक चर्चा उस कथित घटना की है जिसमें एक व्यक्ति ने अपना भुगतान अटकने पर जिला पंचायत सीईओ तक शिकायत पहुंचा दी,शिकायत पहुंचने के बाद संबंधित कर्मचारी का फोन आया,बताया जाता है कि सवाल यह था– सीईओ से फोन क्यों करवाया? सीधे मुझे बोल देते,अब यह सवाल सुनकर लोग भी हैरान हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में शिकायत ऊपर के अधिकारी तक इसलिए पहुंचती है ताकि समस्या का समाधान हो सके,लेकिन यहां शिकायतकर्ता को ही जवाब देना पड़ गया कि उसने शिकायत क्यों की, जनपद के गलियारों में इस घटना को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं।

बस से आते हैं, लेकिन प्रभाव वीआईपी जैसा!

बैकुंठपुर में एक और चर्चा बड़ी लोकप्रिय है,लोग कहते हैं कि देखने में तो सब कुछ बेहद सामान्य है, साधारण जीवनशैली, बस से आना-जाना,कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कोई दिखावटी ठाठ-बाट नहीं,लेकिन प्रभाव ऐसा कि पंचायत प्रतिनिधि उनसे मिलने के पहले दस बार सोचते हैं,जनपद में यह भी चर्चा है कि बस स्टैंड से लाने और छोड़ने तक के लिए अलग कर्मचारी लगाया जाता है,अब यह व्यवस्था क्यों है, किस आधार पर है और इसकी प्रशासनिक आवश्यकता क्या है,यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है।

120 पंचायतें और एक कुर्सी का प्रभाव

बैकुंठपुर जनपद की लगभग 120 पंचायतें मनरेगा से जुड़ी हैं,हर पंचायत में मजदूर हैं, हर पंचायत में विकास कार्य हैं, हर पंचायत में भुगतान की जरूरत है, ऐसे में यदि किसी एक कर्मचारी को लेकर इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आ रही हैं तो सवाल केवल व्यक्ति का नहीं, व्यवस्था का भी है,क्या पूरी प्रणाली किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर हो गई है? क्या कार्यों का उचित विभाजन नहीं है? क्या निगरानी तंत्र कमजोर है? ये वे प्रश्न हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना चाहिए।

चंदन की खुशबू या सिस्टम की बदबू ?

जनपद कार्यालय में इन दिनों लोग व्यंग्य में कहते हैं कि यहां चंदन इतना महक रहा है कि उसकी खुशबू पंचायतों तक पहुंच रही है,लेकिन सवाल यह है कि यह खुशबू वास्तव में चंदन की है या फिर उस व्यवस्था की बदबू है जिसमें पारदर्शिता कम और प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है, यदि आरोप गलत हैं तो उनका खंडन होना चाहिए, यदि आरोप सही हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबसे खराब स्थिति वह होती है जब आरोप भी चलते रहें और जवाब भी न मिले।

मजदूरों के पैसे पर राजनीति नहीं...पारदर्शिता चाहिए...

मनरेगा कोई निजी कारोबार नहीं है,यह गरीब मजदूरों के हक का पैसा है,यह उन लोगों का अधिकार है जो धूप में सड़क बनाते हैं,तालाब खोदते हैं,नाली बनाते हैं और गांवों का विकास करते हैं,यदि उनके भुगतान में देरी होती है तो उसका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ता है,इसलिए भुगतान प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

नोट :- इस समाचार में वर्णित आरोप विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों और सूत्रों द्वारा लगाए गए दावों पर आधारित हैं,संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

एचएमएस यूनियन ने मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा को दी भावभीनी विदाई, नए महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार का किया भव्य स्वागत

काटकोना गेस्ट हाउस में आयोजित समारोह में अधिकारियों,यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारियों की रही बड़ी उपस्थिति

-संवाददाता-
पटना/बैकुंठपुर,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

एचएमएस श्रमिक संगठन द्वारा एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र के काटकोना गेस्ट हाउस में मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा को भावभीनी विदाई एवं नवागत महाप्रबंधक नरेश प्रसाद के स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में बैकुंठपुर क्षेत्र के अधिकारी,विभिन्न इकाइयों के प्रबंधक,यूनियन पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

समारोह की शुरुआत पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्य अतिथियों के स्वागत से हुई, एचएमएस यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा दोनों अतिथियों का माल्यार्पण एवं महामाला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया,पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और आत्मीयता का माहौल बना रहा, कार्यक्रम में बैकुंठपुर क्षेत्र के सब एरिया मैनेजर काटकोना, सब एरिया मैनेजर चरचा, स्टाफ ऑफिसर बैकुंठपुर,खान प्रबंधक चरचा, खान प्रबंधक काटकोना,डॉ. विराजी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे,वहीं एचएमएस श्रमिक संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी भी समारोह में शामिल हुए,स्वागत समारोह के दौरान एरिया अध्यक्ष हरि यादव, एरिया महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, दिनेश शर्मा, अजय सिंह, सुरेश कुशवाहा, ज्ञानेंद्र पांडे, राजेश अग्निहोत्री, रमेश जायसवाल, विजय यादव, डोरी लाल साहू,अशोक निर्मलकर,अनूप कुमार एवं अन्य साथियों ने मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा और नवागत महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार का पुष्पमालाओं से स्वागत किया।

स्वागत भाषण एरिया महामंत्री योगेंद्र मिश्रा द्वारा दिया गया,उन्होंने मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में अनेक विकासात्मक और कर्मचारी हितों से जुड़े कार्य हुए हैं, अपने संबोधन में मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा ने कहा कि उनके चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान एचएमएस श्रमिक संगठन सहित सभी श्रमिक संगठनों का भरपूर सहयोग मिला,उन्होंने कहा कि इसी सहयोग का परिणाम है कि एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में श्रमिक कॉलोनियों की साफ-सफाई,पेयजल व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए कई कार्य किए गए, उन्होंने कहा कि कुछ कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें पूरा किए जाने की आवश्यकता है, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारियों और श्रमिक संगठनों का सहयोग नए महाप्रबंधक को भी मिलता रहेगा, जिससे क्षेत्र में विकास कार्यों और उत्पादन गतिविधियों को और गति मिलेगी।

एचएमएस यूनियन ने जताया सहयोग का भरोसा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एरिया अध्यक्ष हरि यादव ने कहा कि श्रमिक संगठन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ प्रबंधन का सहयोग करता आया है और आगे भी कर्मचारियों एवं क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग जारी रहेगा, उन्होंने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान और उत्पादन वृद्धि दोनों को साथ लेकर चलना संगठन की प्राथमिकता रही है।

नए महाप्रबंधक ने जताया विश्वास

नवागत महाप्रबंधक नरेश प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें बैकुंठपुर क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला है और वे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा श्रमिक संगठनों के सहयोग से क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का सहयोग पूर्व में प्रबंधन को मिलता रहा है, यदि वही सहयोग आगे भी मिलता रहा तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी और क्षेत्र की कार्यक्षमता और मजबूत होगी, उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा किसी भी कर्मचारी के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी।

आत्मीय माहौल में संपन्न हुआ कार्यक्रम-

समारोह के दौरान श्रमिक संगठनों और प्रबंधन के बीच बेहतर समन्वय, उत्पादन वृद्धि और कर्मचारी कल्याण को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई, कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने मुख्य महाप्रबंधक बी.एन. झा को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं तथा नवागत महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार का स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की कामना की।

CMYK

क्या कोरिया में भी सीतापुर जैसे विस्फोट का इंतजार?

स्थायी स्टेनो विवाद पर उबल रहा असंतोष, कलेक्ट्रेट में चर्चा–आखिर किसकी छत्रछाया में चल रहा है यह प्रशासनिक साम्राज्य?

कलेक्टर बदले, सरकार बाले, बदले, अधिकारी बदले, लेकिन नहीं बदला एक नाम, अब सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम

-रवि सिंह-

कोरिया,03 जून 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सीतापुर में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद की गूंज अभी तक थमी नहीं है,सोशल मीडिया से लेकर अखबारों और न्यूज चैनलों तक वह मामला आज भी सुर्खियों में बना हुआ है, उस घटना ने पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया था कि जब प्रशासनिक असंतोष को लंबे समय तक दबाया जाता है, जब शिकायतों को फाइलों में कैद कर दिया जाता है और जब व्यवस्था में संवाद की जगह अहंकार ले लेता है, तब विस्फोट होना तय हो जाता है, लेकिन लगता है कि कोरिया जिले के जिम्मेदार अधिकारी उस घटना से कोई सीख लेने के मूड में नहीं हैं, यही वजह है कि आज कोरिया कलेक्ट्रेट में एक नया सवाल तेजी से गूंज रहा है क्या यहां भी किसी बड़े टकराव या अप्रिय घटना का इंतजार किया जा रहा है?

कलेक्ट्रेट या निजी जागीर?

सरकारी कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी व्यवस्था होती है,लेकिन कोरिया कलेक्ट्रेट में एक ऐसा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे कर्मचारी अब व्यंग्य में स्थायी प्रतिनियुक्ति मॉडल कहने लगे हैं,लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन-सा प्रशासनिक चमत्कार है कि वर्षों से एक ही व्यवस्था कायम है? कलेक्टर आते हैं...कलेक्टर जाते हैं...नई सरकार आती है...नई नीतियां बनती हैं, लेकिन एक नाम और एक कुर्सी का रिश्ता ऐसा है जिसे कोई हिला नहीं पा रहा,कलेक्ट्रेट के गलियारों में मजाक चल रहा है कि कुछ कर्मचारियों का तबादला शासन करता है और कुछ का तबादला शायद भगवान भी नहीं कर सकते।

सीतापुर में झगड़ा हुआ,यहां असंतोष पनप रहा है...

सीतापुर की घटना एक दिन में नहीं हुई थी,उसके पीछे भी लंबे समय से जमा हो रहा असंतोष था,संवादहीनता थी,अधिकारों का टकराव था, व्यवस्था के प्रति नाराजगी थी, और जब वह सब एक सीमा पार कर गया तो मामला पूरे प्रदेश की सुर्खी बन गया,कोरिया कलेक्ट्रेट में भी कर्मचारी वर्ग के बीच इसी प्रकार की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं,लोग खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरखाने नाराजगी की आग सुलग रही है,कई कर्मचारियों का मानना है कि जब किसी एक व्यक्ति का प्रभाव आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो बाकी कर्मचारियों में स्वाभाविक रूप से असंतोष पैदा होता है।

आखिर किस बात का संरक्षण?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि वर्षों से इस मामले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या किसी ने जांच की? क्या किसी ने प्रतिनियुक्ति की फाइल देखी? क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि नियम क्या कहते हैं? या फिर मामला इतना विशेष है कि नियम भी दूरी बनाकर चल रहे हैं? कलेक्ट्रेट परिसर में व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनने को मिल रही है कि शायद इस प्रतिनियुक्ति की फाइल पर कोई ऐसा सुरक्षात्मक कवच चढ़ा हुआ है जिसे प्रशासनिक तलवार छू नहीं पा रही।

संभागायुक्त कार्यालय की खामोशी भी चर्चा में...

अब सवाल केवल जिला प्रशासन तक सीमित नहीं है, लोग पूछ रहे हैं कि सरगुजा संभाग का शीर्ष प्रशासनिक कार्यालय आखिर क्या कर रहा है? यदि मामला चर्चा में है तो जांच क्यों नहीं? यदि शिकायतें गलत हैं तो खंडन क्यों नहीं? यदि शिकायतें सही हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं? संभागायुक्त कार्यालय की चुप्पी अब खुद एक चर्चा का विषय बन चुकी है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या आंखों पर नियमों की पट्टी बंधी है या फिर किसी और कारण से मामला अनदेखा किया जा रहा है?

कर्मचारी पूछ रहे हैं–नियम सबके लिए या चुनिंदा लोगों के लिए?

कलेक्ट्रेट के कर्मचारी खुलकर भले कुछ न कहें,लेकिन उनके बीच एक सवाल बार-बार उठ रहा है, जब अन्य कर्मचारियों के तबादले होते हैं, पदस्थापन बदलते हैं और प्रतिनियुक्तियां समाप्त होती हैं,तब इस मामले में अलग व्यवस्था क्यों? यदि नियम हैं तो उनका पालन क्यों नहीं? और यदि नियम लागू नहीं हैं तो फिर नियम पुस्तिका को संग्रहालय में रख देना चाहिए, कम से कम कर्मचारियों को यह भ्रम तो नहीं रहेगा कि नियम सबके लिए समान हैं।

स्थायी स्टेनो मॉडल प्रशासनिक शोध का विषय बन सकता है

व्यंग्य में कुछ कर्मचारी कहते हैं कि यदि प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान चाहें तो स्थायी स्टेनो मॉडल पर अलग से शोध करवा सकते हैं, क्योंकि यह एक अनूठा प्रयोग है,जहां प्रतिनियुक्ति अस्थायी होकर भी स्थायी है, जहां बदलाव के दौर में भी कुछ नहीं बदलता, जहां चर्चा बहुत होती है लेकिन निर्णय नहीं होता,और जहां शिकायतें भी घूम-फिरकर वहीं पहुंच जाती हैं जहां से शुरू हुई थीं।

क्या किसी बड़े विवाद का इंतजार है?

सबसे गंभीर सवाल यही है की क्या प्रशासन तब जागेगा जब कोई बड़ा विवाद सामने आएगा? क्या तब संज्ञान लिया जाएगा जब मामला सोशल मीडिया की सुर्खी बन जाएगा? क्या तब जांच होगी जब कर्मचारी खुलकर विरोध करने लगेंगे? सीतापुर की घटना ने यह सिखाया था कि प्रशासनिक असंतोष को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है,लेकिन लगता है कि कोरिया में उस सीख को अभी तक फाइलों में ही रखा गया है।

जवाब चाहिए,चुप्पी नहीं...

यह मामला किसी एक कर्मचारी का नहीं रह गया है,यह प्रशासनिक पारदर्शिता का सवाल है,यह कर्मचारियों के विश्वास का सवाल है, यह व्यवस्था की निष्पक्षता का सवाल है,यदि सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए,क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह नहीं होती जब सवाल उठते हैं,सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब सवाल उठते रहें और जवाब देने वाले मौन साध लें,फिलहाल कोरिया कलेक्ट्रेट में सबसे ज्यादा चर्चा किसी फाइल, किसी योजना या किसी आदेश की नहीं, बल्कि इसी सवाल की है क्या प्रशासन किसी समाधान की तैयारी कर रहा है या फिर सीतापुर जैसी किसी नई सुर्खी का इंतजार?

केल्हारी नाईट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज़,गुलाब कमरों के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब

हजारों खेल प्रेमियों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ,तालियों और नारों से गूंज उठा क्रिकेट ग्राउंड

युवाओं के चहेते नेता गुलाब कमरों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

-संवाददाता-
जनकपुर/केल्हारी, 03 जून 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित केल्हारी नाईट क्रिकेट प्रतियोगिता का रविवार को भव्य शुभारंभ हुआ,क्रिकेट प्रेमियों और युवाओं में इस आयोजन को लेकर लंबे समय से उत्साह बना हुआ था, प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर पूर्व विधायक गुलाब कमरों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, उनके केल्हारी क्रिकेट ग्राउंड पहुंचते ही पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट,नारों और उत्साह से गूंज उठा, आयोजन समिति के सदस्यों,खिलाड़ियों और क्षेत्र के हजारों खेल प्रेमियों ने पूर्व विधायक गुलाब कमरों का आत्मीय स्वागत किया,आयोजन समिति के मोहम्मद यूसुफ,अनुज तिवारी,अनिकेत भारती, इमरान, मुन्ना, मोनिश एवं संदीप द्विवेदी सहित अन्य सदस्यों ने पुष्पमालाओं एवं स्वागत समारोह के माध्यम से उनका अभिनंदन किया।

फीता काटकर किया प्रतियोगिता का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ किया और पहले मुकाबले की शुरुआत कराई,उनके मैदान में पहुंचते ही खिलाड़ियों और दर्शकों में विशेष उत्साह देखने को मिला,युवाओं ने जोरदार नारों और तालियों के साथ उनका स्वागत किया। आयोजन स्थल पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।

खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी प्रतियोगिता

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गुलाब कमरों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है,आवश्यकता केवल उन्हें उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन,संघर्ष और टीम भावना विकसित करता है तथा उन्हें सकारात्मक दिशा प्रदान करता है,उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन क्षेत्र के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

युवाओं के बीच दिखी विशेष लोकप्रियता : गुलाब

कमरों की उपस्थिति को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया, क्षेत्र में खेल, शिक्षा, सामाजिक सरोकार और युवाओं के मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाने के कारण वे युवाओं के बीच लोकप्रिय माने जाते हैं, कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने उनके साथ मुलाकात की और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं प्राप्त कीं।

आयोजन समिति ने जताया आभार

आयोजन समिति और खिलाड़ियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मार्गदर्शन युवाओं के उत्साह को बढ़ाता है, उन्होंने पूर्व विधायक गुलाब कमरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके आगमन से प्रतियोगिता को नई ऊर्जा और पहचान मिली है।

बड़ी संख्या में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता

कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामनरेश पटेल, जिला अध्यक्ष मकसूद, शकील, नजारूस एक्का,अमर सिंह,उस्मान सहित कांग्रेस पदाधिकारी,सामाजिक कार्यकर्ता,खेल प्रेमी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे, प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही अब क्षेत्र में क्रिकेट का रोमांच शुरू हो गया है, आगामी दिनों में विभिन्न टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे,जिन्हें देखने के लिए खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

CMYK

जब बॉबी देओल ने मनीषा कोइराला के साथ इंटिमेट सीन देने से किया था मना

बॉबी देओल ने अपने करियर के शुरुआती दिनों के किस्से शेयर किए, जिसमें ट्विंकल खन्ना और रानी मुखर्जी के साथ प्रैंक शामिल हैं। उन्होंने फिल्म गुप्त की शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला के साथ एक इंटिमेट सीन करने से इनकार कर दिया था। बॉबी देओल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1995 में ट्विंकल खन्ना के अपोजिट फिल्म बरसात से की थी। ये फिल्म एक बड़ी कॉमर्शियल सक्सेस साबित हुई थी। इसके बाद, उन्होंने काजोल और मनीषा कोइराला के साथ गुप्ता, रानी मुखर्जी के साथ बिच्छू,प्रीति जिंटा के साथ सोल्जर जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हाल ही में एक इंटरव्यू में, बॉबी ने शूटिंग के उन दिनों को याद किया जब वो सेट पर अपनी को-एक्ट्रेस के साथ उन्हें परेशान करने के लिए कई तरह के प्रैंक किया करते थे। बॉबी ने उस समय के कई किस्से सुनाए जिनमें से एक किस्सा बहुत ही मजेदार है।

ट्विंकल खन्ना को करते थे परेशान

आप की अदालत के एक एपिसोड में बॉबी देओल से सवाल किया गया कि बरसात की शूटिंग के दौरान वो ट्विंकल खन्ना से बहुत लड़ते थे? इस इस पर उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से पेट की दिक्कत रहती है। मैं बचपन से इसके बारे में बात करता रहता था कि आज ये हुआ,आज वो हुआ या कुछ भी। इससे ट्विंकल इरिटेट हो जाती थी।

रानी मुखर्जी को बुलाते थे डेढ़ फुटिया

इसके अलावा बॉबी देओल रानी मुखर्जी को डेढ़ फुटिया कहकर चिढ़ाते थे। हालांकि दोनों ही एक्टर के बीच में गहरी दोस्ती है और ये मस्ती मजाक उनके बीच एक आम बात है। इसके बाद बॉबी देओल से पूछा गया कि आपने मनीषा कोइराला के साथ इंटीमेट सीन करने से इनकार कर दिया था। आपने कहा था कि इनके मुंह से बदबू आती है। इस सवाल का बॉबी देओल ने हां में उत्तर दिया।

मनीषा कोइराला के साथ शूटिंग के लिए किया मना

दरअसल ये वाक्या साल 1997 में फिल्म गुप्त की शूटिंग के दौरान का है। इस फिल्म में काजोल और मनीषा कोइराला ने लीड रोल निभाया था। बॉबी ने इस पर बात करते हुए कहा, हां, मुझे याद है। शूटिंग के दौरान ठंड थी। एक व्यक्ति वहां चना जोर गरम बेच रहा था और मनीषा ने उसे बड़े चाव से खाया। एक सीन शूट होना बाकी था। इस गाने के दौरान उसे मेरी ठोड़ी पर काटना था लेकिन उनके मुंह से प्याज की बदबू आ रही थी जिसकी वजह से मैं एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था। उसके मुंह से प्याज की बदबू के कारण मैं कोई भाव नहीं दे पा रहा था। मैं उससे बदला कैसे लेता? वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉबी देओल बहुत जल्द अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर में नजर आएंगे। यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा, वह इस साल के अंत में वाईआरएफ की फिल्म अल्फा में आलिया भट्ट और शरवरी के साथ भी दिखाई देंगे।

पद्मिनी कोल्हापुरे : 80 के दशक की यादगार अभिनेत्री

80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार की थी। बहुत कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली पद्मिनी ने जल्द ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग और मासूम खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली। पद्मिनी कोल्हापुरे न सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने भी उन्हें उस दौर की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। उनकी फिल्मों में इंसाफ का तराजू, आहिस्ता-आहिस्ता और प्यार झुकता नहीं जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इन फिल्मों में उनके किरदारों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई। पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपने अभिनय से यह साबित किया कि वह सिर्फ ग्लैमर का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक गंभीर और प्रतिभाशाली कलाकार भी हैं। उन्होंने हर किरदार को बेहद सहजता और भावनात्मक गहराई के साथ निभाया, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। 80 के दशक में जब बॉलीवुड अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा था, उस समय पद्मिनी कोल्हापुरे जैसी अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री को नई पहचान दी। उनकी फिल्मों में दिखने वाला सादगी और भावनात्मक अभिनय आज भी दर्शकों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि उनकी फिल्में और किरदार आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें एक यादगार अभिनेत्री के रूप में देखा जाता है। संक्षेप में, पद्मिनी कोल्हापुरे 80 के दशक की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, प्रतिभा और खूबसूरती के दम पर बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें एक आइकॉनिक एक्ट्रेस के रूप में याद किया जाता है।

केजीएफ 2 के बाद बदल गया बॉलीवुड का एक्शन स्टाइल

बीते 10 सालों में बॉलीवुड फिल्मों में एक्शन दिखाने का तरीका काफी हद तक बदल गया है। एक समय था जब हिंदी फिल्मों में पारंपरिक ढिशूम-ढिशूम स्टाइल एक्शन देखने को मिलता था, जिसमें बड़े ही सरल और नाटकीय अंदाज में फाइट सीन्स फिल्माए जाते थे। उस दौर में साउथ सिनेमा के एक्शन स्टाइल का अक्सर मजाक भी उड़ाया जाता था।

लेकिन समय के साथ भारतीय सिनेमा का स्वरूप बदलता गया। खासकर साल 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म केजीएफ- चैप्टर 2 ने इस बदलाव को नई दिशा दी। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि एक्शन की परिभाषा को भी पूरी तरह बदल दिया। केजीएफ 2 में दिखाए गए हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक और ग्रैंड विजुअल्स ने दर्शकों को एक नया अनुभव दिया। इस फिल्म के बाद भारतीय सिनेमा में एक्शन को लेकर सोच बदल गई और अब बड़े बजट की फिल्मों में रियलिस्टिक और पावरफुल एक्शन पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि केजीएफ 2 ने यह साबित किया कि दर्शक अब पुराने ढर्रे के एक्शन से आगे बढ़ चुके हैं और वे ज्यादा इंटेंस, विजुअली स्ट्रॉन्ग और इंटरनेशनल लेवल का कंटेंट देखना चाहते हैं। इसके बाद बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्रीज ने भी अपने प्रोडक्शन स्टाइल में बदलाव करना शुरू कर दिया। आज के समय में कई फिल्में साउथ इंडस्ट्री के एक्शन स्टाइल से प्रेरित होकर बनाई जा रही हैं। बड़े सेट, एडवांस व्हीएफएक्स और मजबूत कहानी के साथ एक्शन को ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। केजीएफ 2 की सफलता ने यह भी दिखाया कि भाषा अब बाधा नहीं रही, बल्कि कंटेंट और प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस फिल्म ने पूरे देश में पैन-इंडिया सिनेमा के ट्रेंड को और मजबूत किया।

तीसरी बार शादी करने के लिए तैयार आमिर खान ? गौरी स्प्रैट को इस दिन बनाएंगे अपना हमसफर

आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की तैयारी में हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शादी एक निजी समारोह होगी जिसमें परिवार के कुछ सदस्य ही मौजूद रहेंगे। आमिर खान और उनकी पार्टनर गौरी स्प्रैट अपने रिलेशनशिप को दूसरे लेवल पर ले जाने की तैयारी में हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान और गौरी शादी करने वाले हैं।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमिर खान और गौरी कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। पिछले साल अपने 60 वें जन्मदिन पर आमिर ने गौरी को मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाया था। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर ही एक प्राइवेट सेरेमनी के तौर पर रखी जाएगी। एक्टर का लैविश वेडिंग करने का कोई प्लान नहीं है। शादी में कुछ करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल होंगे। हॉटरफ्लाई की जानकारी के अनुसार शादी एकदम इंटीमेट होगी। शादी की डेट 5 जुलाई बताई जा रही है। पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में आमिर ने अपने और गौरी के रिश्ते पर बात की थी। आमिर ने कहा था-गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर बेहद गंभीर हैं और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। हम पार्टनर्स हैं। हम साथ हैं। शादी की बात करें तो, दिल से तो मैं उससे पहले ही शादी कर चुका हूं। इसलिए, हम इसे औपचारिक रूप देंगे या नहीं, यह मैं समय के साथ तय करूंगा। आमिर खान 60 साल के हैं जबकि गौरी की उम्र 46 साल है। दोनों के बीच 14 साल का ऐज गैप है। दोनों को अक्सर कई इवेंट्स में साथ में देखा जाता है। गौरी से पहले आमिर खान की शादी किरण राव के साथ हुई थी। दोनों ने साल 2005 में शादी की थी। इस शादी से उन्हें एक बेटा आजाद है। शादी के 16 साल बाद आमिर खान ने पत्नी किरण से 2021 में तलाक ले लिया था। किरण और आमिर अभी भी अच्छे दोस्त हैं।

करियर में वापसी कर रहीं रिया चक्रवर्ती को मिला उर्फी का समर्थन

टेलीविज़न एक्ट्रेस ऊर्फी जावेद ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद आई मुश्किलों से पार पाने और अपने करियर को नए सिरे से बनाने के लिए रिया चक्रवर्ती की तारीफ़ की। ऊर्फी ने रिया की फिर से अपना नाम बनाने के लिए तारीफ़ की और माना कि उन्हें एक बार लगा था कि रिया का करियर खत्म हो गया है। हालांकि, रिया ने एक फाउंडर और एंटरप्रेन्योर के तौर पर खुद को फिर से खड़ा किया है। वैरायटी इंडिया से बात करते हुए, ऊर्फी ने कहा, ईमानदारी से कहूं तो, अगर मैं वहां होती,तो सोचती, अब सब कुछ खत्म हो गया है। फिर उन्होंने रिया की तारीफ़ करते हुए कहा,लेकिन जिस तरह से वह [रिया] इससे बाहर निकलीं? उन्होंने इतना अच्छा ब्रांड बनाया है।

उन्होंने फिर से अपने लिए एक नाम बनाया है। ऊर्फी ने आगे कहा कि जब सुशांत के आस-पास सब कुछ सामने आ रहा था, तो उन्हें लगा कि रिया का करियर खत्म हो गया है। खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूती से फिर से बनाने के लिए उनकी तारीफ़ करते हुए, ऊर्फी ने कहा, मैंने सोचा था, यह नामुमकिन है। उनका करियर खत्म हो गया है। लेकिन उन्होंने कर दिखाया, यार। उस लेडी में दम है। हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करते हुए, रिया ने अपना पॉडकास्ट चैनल,चैप्टर 2 शुरू किया। उन्होंने अपने भाई,शोविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर चैप्टर 2 ड्रिप नाम का एक स्ट्रीटवियर कपड़ों का ब्रांड भी शुरू किया है।

खेल समाचार

सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम न्यूयॉर्क निक्स,ऐतिहासिक टकराव की तैयारी

सेंटियागो,03 जून 2026। 2025-26 एनबीए सीज़न अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है, और बास्केटबॉल प्रेमियों की निगाहें अब एनबीए फ़ाइनल पर टिक गई हैं। इस साल का फ़ाइनल मुकाबला दो ऐतिहासिक फ़्रैंचाइज़ियों–सैन एंटोनियो स्पर्स और न्यूयॉर्क निक्स–के बीच होगा। दोनों टीमें इस प्रतिष्ठित सीरीज़ में जीत हासिल करके अपनी टीम के इतिहास में

एक और चैंपियनशिप बैनर जोड़ने की कोशिश करेंगी। सैन एंटोनियो स्पर्स ने पश्चिमी कॉन्फ़्रेंस फ़ाइनल में एक रोमांचक सात-गेम सीरीज़ में ओक्लाहोमा सिटी थंडर को हराकर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की। टीम की सफलता में मुख्य योगदान रहा उनके उभरते सुपरस्टार विक्टर वेम्बान्यामा का,जिनकी लीडरशिप और खेल के प्रति रणनीतिक समझ ने टीम को महत्वपूर्ण मौकों पर जीत दिलाई। स्पर्स के फैंस लंबे समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और उनकी टीम ने फिर से फ़ाइनल में पहुँचकर उम्मीदों पर खरा उतरा है। वहीं, ईस्टर्न कॉन्फ़्रेंस की दावेदार न्यूयॉर्क निक्स ने क्लीवलैंड कैवेलियर्स को हराकर फ़ाइनल की ओर रास्ता बनाया। निक्स के लिए यह फ़ाइनल एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वे दशकों में पहली बार एनबीए फ़ाइनल में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। टीम की मजबूती, रणनीतिक खेल और प्रमुख खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्हें इस कठिन चुनौती में लाकर खड़ा कर रहा है।

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी

नई दिल्ली,03 जून 2026। एक अहम प्रशासनिक फैसले में नई बनी पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है। राज्य के सुरक्षा विभाग ने व्यापक सुरक्षा पुनर्मूल्यांकन

और थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस के बाद यह निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार, सौरव गांगुली को पहले वर्ष 2023 में 'जेड' कैटेगरी से बढ़ाकर वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की गई थी। उस समय उनके संभावित खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा स्तर में यह बढ़ोतरी की गई थी। “’ कैटेगरी के तहत उन्हें उच्च स्तरीय सुरक्षा कवर दिया गया था,जिसमें 8 से 10 पुलिसकर्मियों की टीम उनकी सुरक्षा में तैनात रहती थी। इसके अलावा जब भी वे राज्य के भीतर यात्रा करते थे, तो हथियारबंद एस्कॉर्ट टीम उनके साथ रहती थी।

विराट कोहली और रोहित शर्मा भी पहुंचेंगे मुल्लांपुर

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम का हिस्सा न होने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली 9 से 11 जून तक मुल्लांपुर में लगने वाले प्री-सीजन कैंप का हिस्सा बनेंगे...यह कैंप 13 जून से धर्मशाला में शुरू होने वाली वनडे सीरीज की तैयारियों के लिए लगाया जा रहा है...

नई दिल्ली,03 जून 2026। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टेस्ट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए मुल्लांपुर पहुंच चुकी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से काफी पहले ही संन्यास ले चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि टेस्ट मैच का हिस्सा न होने के बावजूद विराट,रोहित और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज जल्द ही मुल्लांपुर पहुंचने वाले हैं। चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने इन सीनियर खिलाड़ियों के लिए एक खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत टेस्ट मैच के दौरान ही ये खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते नजर आएंगे।

13 जून से वनडे सीरीज, चंडीगढ़ में लगेगा प्री-सीजन कैंप

दरअसल, अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खत्म होने के बाद भारत को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसका पहला मुकाबला 13 जून को धर्मशाला में खेला जाएगा। वनडे सीरीज की तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बीसीसीआई ने मुल्लांपुर में एक स्पेशल प्री-सीजन कैंप आयोजित करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे व्हाइट-बॉल के दिग्गज 9 से 11 जून तक मुल्लांपुर की मॉडर्न फैसिलिटी में ट्रेनिंग करेंगे। इस तीन दिवसीय कैंप के खत्म होने के बाद पूरी वनडे टीम धर्मशाला के लिए उड़ान भरेगी।

युवाओं को मिलेगा दिग्गजों का साथ

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टेस्ट स्क्वॉड में शामिल कुछ सीनियर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ टेस्ट मैच खत्म होने के बाद वहीं रुकेंगे, ताकि वे 9 से 11 जून के इस तैयारी वाले विंडो में वनडे स्क्वॉड की मदद कर सकें। इसके अलावा, नेट बॉलर के तौर पर शामिल प्रिंस यादव के लिए यह सफर बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि वे टेस्ट कैम्प में नेट बॉलिंग की जिम्मेदारी संभालने के बाद सीधे मुख्य वनडे टीम के साथ जुड़ जाएंगे।

मोहम्मद सिराज के खेलने पर सस्पेंस

इस बीच टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की मौजूदगी को लेकर संशय बना हुआ है। मेडिकल स्टाफ और टीम मैनेजमेंट अगले 48 घंटों में उनके वर्कलोड को लेकर आखिरी फैसला करेगा। सिराज हाल ही में खत्म हुए आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए थका देने वाले सीजन से गुजरे हैं। उन्होंने 31 मई को आरसीबी के खिलाफ हुए फाइनल समेत गुजरात के सभी मैच खेले हैं। ऐसे में उन्हें रेड-बॉल क्रिकेट से आराम दिया जा सकता है। फिलहाल आकिब नबी, गुरजापनीत सिंह, प्रिंस यादव, सारांश जैन, जीशान अंसारी और शिवांग कुमार के साथ उन 6 नेट बॉलर्स के ग्रुप का हिस्सा हैं, जो मुल्लांपुर में भारतीय बल्लेबाजों को अभ्यास करा रहे हैं।

बीसीसीआई ने नेशनल टीम के नेट्स में बॉलिंग के लिए सात खिलाड़ियों को किया शामिल

नई दिल्ली,03 जून 2026। आईपीएल 2026 के खत्म होने के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों का ध्यान नेशनल टीम पर केंद्रित हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ के लिए टीम इंडिया के बैटर्स को नेट्स में बॉलिंग कराने हेतु कुल सात खिलाड़ियों को बुलाया है। यह तैयारी अफ़गानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच से पहले की गई है। सूत्रों के मुताबिक, इस नेट्स सेशन में जम्मू और कश्मीर के तेज़ गेंदबाज़ औकिब नबी डार और उत्तर प्रदेश के लेग-स्पिनर ज़ीशान अंसारी समेत कुल सात गेंदबाज़ शामिल होंगे। इन गेंदबाज़ों को मुख्य रूप से टीम इंडिया के बैटिंग विभाग को बेहतर तैयारी देने के लिए चुना गया है, ताकि खिलाड़ी अफ़गानिस्तान की तेज़ और स्पिन गेंदबाज़ी का सामना करने के लिए प्रैक्टिस कर सकें।

औकिब नबी डार ने आईपीएल 2026 और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया था। उनके चयन न होने को लेकर क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा और आलोचना हुई थी। बीसीसीआई ने अब उनका उपयोग नेट्स बॉलिंग के लिए किया है, जिससे उनकी क्षमताओं का फायदा टीम को तैयारियों के दौरान मिल सके। टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला इसलिए भी लिया है ताकि टेस्ट सीरीज़ में बैटर्स को विभिन्न प्रकार की गेंदबाज़ी का सामना करने का अनुभव हो सके। नेट्स में खेलते समय खिलाड़ियों को अलग-अलग पेस और स्पिन परिस्थितियों का सामना कराया जाएगा,जिससे वे मैच के दौरान किसी भी प्रकार की गेंदबाज़ी के लिए तैयार रहें। इस तैयारी से टीम इंडिया की अफ़गानिस्तान सीरीज़ में रणनीति मजबूत होने की उम्मीद है। भारतीय टीम के बैटर्स नेट्स सेशन के दौरान तेज़, मीडियम और स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ अपनी तकनीक पर काम कर सकेंगे। इस सेशन में शामिल सात खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य बल्लेबाज़ों को चुनौती देना और उनके फ़ॉर्म को टेस्ट मैच के लिए सटीक बनाना है। बीसीसीआई की इस पहल से युवा और घरेलू क्रिकेटरों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी का अनुभव मिलेगा।

CMYK

तीन बार राजपत्र भी हार गया? खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में नियमों को कुचलकर बांटी गईं नियुक्तियां!

तीन बार राजपत्र हारा और स्थापना जीती,चौथी बार भी स्थापना के जितने की उम्मीद?

तीन बार पदोन्नति में लगभग 15 को फायदा, चौथी बार 17 और लाइन में...जून के पहले सप्ताह में सूची आने की संभावना

फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए चाहिए थी योग्यता, लेकिन विभाग में चल पड़ा 'सेटिंग मॉडल'!

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में फूड टेस्ट से पहले डिग्री टेस्ट जरूरी नहीं?

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए चाहिए थी तकनीकी योग्यता,लेकिन विभाग में चल पड़ा 'नेटवर्क मॉडल'!

- नियम एक तरफ,सेटिंग एक तरफ, खाद्य विभाग में नियुक्तियों का हाई प्रोफाइल खेल
- फूड सेफ्टी विभाग में 'मिलावटी योग्यता' का आरोप, स्थापना शाखा पर गंभीर सवाल
- FSSAI के नियमों को दरकिनार कर बांटी गईं नियुक्तियां?
- तकनीकी डिग्री जरूरी थी,फिर कैसे बने नमूना सहायक खाद्य सुरक्षा अधिकारी?
- राजपत्र में अलग नियम,विभाग में अलग सिस्टम, खाद्य विभाग की नियुक्तियां विवादों में...

फर्जी डिग्री,प्रमोशन और संरक्षण का खेल,खाद्य विभाग में बड़ा भर्ती विवाद

क्या मिलावटी तेल पकड़ने वाला विभाग खुद 'मिलावटी डिग्री' में फंसा?

राजपत्र ने कहा बायोटेक्नोलॉजी, विभाग बोला-चलो जनरल बीएससी भी चलेगी!

रायपुर 03 जून 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इन दिनों ऐसे विवादों के भंवर में फंसा दिखाई दे रहा है, जिसने सिर्फ विभागीय कार्यप्रणाली ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस विभाग को जनता के खाने-पीने की गुणवत्ता की निगरानी करनी थी,वही विभाग अब अपनी नियुक्तियों और अधिकारियों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है,आरोप इतने गंभीर हैं कि यदि इनकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो विभाग के भीतर वर्षों से चल रही कथित सेटिंग संस्कृति का पूरा चेहरा सामने आ सकता है। मामला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) और जिला अधिकारी (डीओ) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन का है, आरोप है कि विभाग में कई ऐसे लोगों को नियुक्ति और पदोन्नति दी गई जिनकी शैक्षणिक योग्यता भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं थी, इससे भी बड़ा आरोप यह है कि स्थापना शाखा में बैठे अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करते हुए कथित रूप से लेनदेन, प्रभाव और संरक्षण के आधार पर अपात्र लोगों को पात्र बना दिया, अब सवाल सिर्फ नियुक्तियों का नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन चुका है कि आखिर छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में चलता क्या है राजपत्र या 'स्थापना व्यवस्था '?

धारा 91 से शुरू होती है पूरी कहानी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट), 2006 की धारा 91 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है, इसी शक्ति के तहत केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 तथा बाद में खाद्य सुरक्षा और मानक (पहला संशोधन) नियम, 2022 जारी किए,इन नियमों में फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर और डेज़िग्नेटेड ऑफिसर की पात्रता स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई, नियम 2.1.2 नामित अधिकारी (डीओ) से संबंधित है, जबकि नियम 2.1.3 विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) की योग्यता निर्धारित करता है, नियम 2.1.3 के तहत एफएसओ के लिए निम्न तकनीकी विषयों में स्नातक,मास्टर या डॉक्टरेट की डिग्री अनिवार्य रूप से निर्धारित है एक दिन और हमेशा के लिए, डेयरी प्रौद्योगिकी,जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव-रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान,रसायन विज्ञान दवा यानी नियम साफ थे, पात्रता स्पष्ट थी, गजट अधिसूचना सार्वजनिक थी। फिर भी सवाल यह उठ रहा है कि अंतिम पात्र लोगों को कैसे मिला?

योग्यता नहीं,जुगाड़ चाहिए विभाग में चल रही सबसे बड़ी चर्चा...

विभागीय सूत्रों का दावा है कि कई नियुक्तियां ऐसी हुईं जिनमें एफएसएसएआई के निर्धारित विषयों और वास्तविक डिग्रियों का मेल ही नहीं था, कहीं सामान्य बीएससी को तकनीकी डिग्री की तरह स्वीकार किया गया, कहीं डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त संदिग्ध डिग्रियों को मान्यता दी गई और कहीं ऐसे विषयों को पात्र मान लिया गया जिनका फ़ूड सेफ्टी से सीधा संबंध ही नहीं था,विभागीय गलियारों में अब व्यंग्य में कहा जा रहा है यहां फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए फूड टेक्नोलॉजी नहीं,सही टेक्नोलॉजी चाहिए,एक अन्य कर्मचारी ने तंज कसते हुए कहा जो विभाग मिलावटी खाद्य पदार्थ पकड़ता है, वहां पहले मिलावटी डिग्रियां पकड़नी चाहिए।

स्थापना शाखा पर उठे सबसे बड़े सवाल

अब पूरा विवाद सिर्फ नियुक्ति पाने वालों पर नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर केंद्रित हो गया है जो स्थापना शाखा में बैठे रहे और जिन्होंने इन फाइलों को मंजूरी दी, क्योंकि कोई भी नियुक्ति अकेले नहीं होती, दस्तावेज जांचे जाते हैं,योग्यता सत्यापित होती है, नियमों से मिलान होता है,नोटशीट तैयार होती है, फिर आदेश जारी होता है,ऐसे में यदि अपात्र लोगों को नियुक्ति मिली,तो सवाल उन सभी पर उठते हैं जिन्होंने इन फाइलों को आगे बढ़ाया,विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि वर्षों तक इन मामलों पर पर्दा डाला गया। किसी ने निष्पक्ष जांच कराने का प्रयास नहीं किया। उल्टा संरक्षण दिया गया, एक कर्मचारी ने व्यंग्य में कहा यहां राजपत्र नहीं,स्थापना शाखा अंतिम सत्य है।

सवालों के घेरे में ये नियुक्तियां

1. **सवेश यादव-** आरोप है कि वर्ष 2016 में विनायक यूनिवर्सिटी, सेलम तमिलनाडु से डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से एमएससी डिग्री प्राप्त की गई, अब सवाल यह है कि क्या उक्त डिग्री उस समय एफएसओ की तकनीकी पात्रता के अनुरूप थी?
2. **सिद्धार्थ पांडे-** इनकी बी टेक बायोटेक्नोलॉजी डिग्री स्ब्रज्ञस इलाहाबाद से बताई जा रही है, विभागीय हलकों में चर्चा है कि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और डिग्री की वैधता तथा पात्रता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ।
3. **दीपक दितलहार-** आरोप है कि इनके पास केवल सामान्य बीएससी डिग्री थी जबकि बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयगत डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद एफएसओ पद के लिए पात्रता कैसे तय की गई, यह सवाल बना हुआ है।
4. **संतोष ध्रुव-** एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर से प्राप्त बताई गई,आरोप यह है कि संबंधित समय में डिस्टेंस लर्निंग की यूजीसी मान्यता को लेकर विवाद था।
5. **शंखनाथ भोई-** एमएटी यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री की डिग्री लेने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं,आरोप है कि जिस समय डिग्री ली गई,उस दौरान डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता साफ नहीं थी।
6. **शाश्वत तिवारी-** बताया जा रहा है कि आवश्यक विषयगत योग्यता और प्रमोशन के लिए आवश्यक सीआर अवधि को लेकर भी सवाल हैं।
7. **रामप्रकाश जयसवाल-** जनरल बीएससी डिग्री के बावजूद एफएसओ पात्रता दिए जाने को लेकर विभाग में चर्चाएं हैं।
8. **फणीभूषण जयसवाल-** बीई इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य बीएससी डिग्री के आधार पर एफएसओ पात्रता कैसे तय हुई, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है।

क्या पैसे लेकर बनाई गई नई 'योग्यताएं'?

सबसे गंभीर आरोप यही हैं कि कथित रूप से लेनदेन और प्रभाव के आधार पर पात्रता की 'नई व्याख्या' तैयार की गई,यानी राजपत्र में तकनीकी डिग्री मांगी गई, लेकिन विभागीय स्तर पर सामान्य डिग्री को भी 'अनुकूल' मान लिया गया,सूत्रों का दावा है जहां नियम अटकते थे, वहां नोटशीट रास्ता बना देती थी, यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार माना जाएगा।

धारा 94 और राज्य सरकार की भूमिका

इस पूरे विवाद में धारा 94 की भी चर्चा हो रही है,यह धारा राज्य सरकार को भर्ती नियम बनाने की शक्ति देती है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया और प्रमोशन प्रतिशत तय कर सकती है,लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम तकनीकी पात्रता समाप्त नहीं कर सकती,यानी राज्य भर्ती नियम बना सकता है,पर एफएसओ की मूल योग्यता नहीं बदल सकता।

2026 संशोधन ने क्यों बढ़ाई हलचल?-

5 मई 2026 को छत्तीसगढ़ शासन ने भर्ती नियमों में संशोधन किया, इस संशोधन में Schedule-II के Executive वर्ग में भर्ती अनुपात '90%-10%' से बदलकर '75%-25%' किया गया, अब विभाग में यह चर्चा तेज है कि क्या इस बदलाव का उपयोग कुछ विशेष लोगों को प्रमोशन और लाभ देने के लिए किया गया? क्योंकि संशोधन के बाद पुराने विवाद फिर से चर्चा में आने लगे।

जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा सबसे बड़ा संकट

विडंबना देखिए जिस विभाग को जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाना था, वही विभाग अब 'मिलावटी योग्यता' के आरोपों में घिरा हुआ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर कोई साधारण पद नहीं है, यही अधिकारी खाद्य पदार्थों के सैंपल लेते हैं, मिलावट की जांच करते हैं,लाइसेंस निरीक्षण करते हैं, जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ऐसे पदों पर यदि विवादित योग्यता वाले लोग बैठेंगे तो पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

विभाग के भीतर सबसे चर्चित व्यंग्य

विभाग में इन दिनों कई तीखे व्यंग्य चल रहे हैं, कोई कहता है यहां फूड टेस्ट से पहले डिग्री टेस्ट होना चाहिए, दूसरा बोलता है खाद्य विभाग में अब नियम नहीं, नेटवर्क काम करता है, और तीसरी लाइन सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है राजपत्र जनता को दिखाने के लिए है,असली नियम फाइलों में बनते हैं।

क्या होगी निष्पक्ष जांच?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्या इन नियुक्तियों और प्रमोशन की स्वतंत्र जांच होगी? क्या यह जांच होगी कि डिग्रियां वैध थीं या नहीं? यूजीसी मान्यता थी या नहीं? विषय एफएसएसएआई नियमों के अनुरूप थे या नहीं? स्थापना शाखा ने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की या नहीं? भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया में कथित लेनदेन हुआ या नहीं? यदि निष्पक्ष जांच हुई तो विभाग के कई बड़े नाम मुश्किल में आ सकते हैं।

अंत में सबसे बड़ा सवाल

क्या छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में कानून चलता है या व्यवस्था ? क्योंकि यदि केंद्र सरकार का राजपत्र, एफएसएसएआई के नियम और तकनीकी पात्रता भी विभागीय सेटिंग के आगे घुटने टेक दें, तो फिर जनता कैसे भरोसा करे कि उसके खाने की सुरक्षा सही हाथों में है? फिलहाल विभाग के गलियारों में सबसे ज्यादा यही लाइन गूंज रही है यहां नियम नहीं, रिश्ता और व्यवस्था काम करती है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस बी.के.एस. का निधन

रिटायरमेंट के बाद लिखीं 50 से ज्यादा किताबें

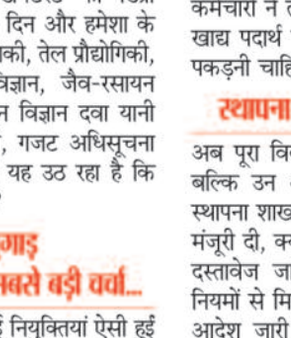

रायपुर,03 जून 2026। घंटे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव और 1972 बैच के आईएएस अधिकारी बी.के.एस. रे का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक और साहित्य जगत में शोक की लहर है। वे लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में सक्रिय रहे और रिटायरमेंट के बाद साहित्य लेखन में पूरी तरह जुट गए थे। बी.के.एस. रे का जन्म 1 जून 1949 को हुआ था। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। साल 2009 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने साहित्य को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया। बी.के.एस. रे ने अपने साहित्यिक जीवन में 50 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनके उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक और समसामयिक विषयों पर आधारित लेखन काफी चर्चित रहे। उनकी रचनाओं में प्रशासनिक अनुभव, सामाजिक सरोकार और भ्रष्टाचार विरोधी विषयों की झलक दिखाई देती थी। उनकी चर्चित पुस्तकों में The Boy from Bhubaneswar, The Blind Horizon, The Turmoil और कविता संग्रह Something Goes Beyond Me शामिल हैं। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें साल 2019 में ग्रीस में 'सुकरात अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया था। प्रशासनिक मामलों और नीतियों पर भी वे विशेषज्ञ टिप्पणीकार के रूप में अपनी राय रखते थे। उनके निधन पर प्रशासनिक अधिकारियों,साहित्यकारों और सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि दी है।

CGPSC घोटाला...पूर्व परीक्षा नियंत्रक वासनिक के घर रेड

राजनांदगांव में भी ईडी की दबिश,रिटायर्ड आईएएस के ठिकानों पर छापे,दस्तावेजों की जांच

दुर्ग भिलाई,03 जून 2026। CGPSC भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में ईडी ने रायपुर, दुर्ग-भिलाई और राजनांदगांव में छापेमारी की है। पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित घर में कार्रवाई चल रही है। वहीं रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 स्थित घर पर जांच जारी है। बता दें कि जेके ध्रुव सीजी-पीएससी भर्ती घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं। इस कार्रवाई को भारतमाला घोटाला मामले में उनके कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। वहीं राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो के भिलाई तालपुरी स्थित निवास पर भी जांच चल रही है। बता दें कि उनकी बेटी नेहा का 13वीं रैंक और बेटे निखिल का 17वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था। राजनांदगांव में तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर के घर पर भी छापा मारा गया है। गणवीर इस मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। ईडी की करीब आठ अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। घर के अंदर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह मामला 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है। आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को दरकिनार कर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर अपने नजदीकी लोगों को पद दिलवाने का खेल हुआ। प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी। जांच एजेंसी ने छापेमारी में कई दस्तावेज और आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए हैं।

टामन सिंह ने रिश्तेदारों और करीबियों को लाभ पहुंचाया

सीबीआई ने दलील दी कि, साल 2020 से 2022 के बीच आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई। आरोप है कि तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रिश्तेदारों और करीबी लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया। जांच में सामने आया कि एक निजी कंपनी से सीएसआर मद के तहत 45 लाख रुपए एक एनजीओ को दिए गए। जिसकी अध्यक्ष सोनवानी की पत्नी थीं। इसके बदले प्रश्नपत्र लीक किए गए।

प्रश्न पत्र लीक करने में रही प्रमुख भूमिका

सीबीआई का यह भी आरोप है कि, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और डिप्टी परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर ने अध्यक्ष के निर्देश पर उद्योगपति श्रवण गोयल को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए। जिन्होंने आगे यह प्रश्नपत्र अपने बेटे और बहू को दिए। दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ। वहीं, सोनवानी के भतीजों का चयन डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी पद पर हुआ।

छत्तीसगढ़ : 500 तहसीलदारों की हड़ताल, दफ्तरों में भटकते रहे लोग

बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग

रायपुर,03 जून 2026। छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा तहसीलदार आज हड़ताल पर हैं। राजस्व कामकाज बंद कर अधिकारियों ने सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप है कि एमएलए ने सरगुजा जिले के नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई की थी। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज प्रदेशभर के तहसीलदार राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। हड़ताल के कारण राज्य की अधिकांश तहसीलों में कामकाज पूरी तरह ठप है। लोग राजस्व कामकाज के लिए भटकते दिखाई दिए। इस पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल उठाते हुए सरकार पर विधायक को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं, वकीलों ने हड़ताल का विरोध किया है, पटवारी संघ ने समर्थन दिया है। बीजेपी ने जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही। बता दें कि इससे पहले 30 मई को कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने हड़ताल की थी। तब विधायक ने खुद गिरफ्तारी देने की बात कही थी। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं होने पर आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक रामकुमार टोप्पो का आरोप है कि, नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने उनकी चचेरी बहन से अभद्रता की थी। तुषार मानिक का आरोप है कि, बहन के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए विधायक और उनके समर्थकों ने उनकी पिटाई की थी। बाद में दोनों पक्षों की शिकायत के बाद काउंटर एफआईआर हुई थी। इसी के बाद राज्य के सभी तहसीलदार एकजुट हुए और कामकाज बंद कर विधायक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधायक समर्थकों ने भी नायब तहसील को हटाने की मांग की है। हड़ताल पर सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि 7 दिन बाद भी एफआईआर के बावजूद विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)